प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 555/2019

निर्णय सुरक्षित किया गया : 12.09.2025

निर्णय पारित किया गयाः24.09.2025

1 – सरिता बाई अनंत पिता फोटोलाल अनंत,28 वर्ष, निवासी भिलाई बाजार, चौकी–हरदीबाजार, जिला–कोरबा, छत्तीसगढ़

2 – श्रीमती. रेशम बाई कुर्रे पति राम निहोरा कुर्रे लगभग 40 वर्ष निवासी चोरहादेवी, पुलिस स्टेशन–कोटा, निवासी–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3 – धीरेंद्र कुमार बघेल पिता राजकुमार 27 वर्ष निवासी गाँव–बडगाहन, पंतोरपारा, पुलिस स्टेशन–बलौदा,जिला–जांजगीर चंपा, छत्तीसगढ़

--- अपीलकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस स्टेशन–कुसमुंडा, जिला–कोरबा, छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 576/2019

राजू दास महांत पिता मंघन दास महांत 32 वर्ष निवासी गाँव देवगांव, पुलिस स्टेशन–दीपका, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य , थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना कुसमुंडा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 848/2019

राजा @रामाशंकर पटेल पिता जगतराम 20 वर्ष निवासी रेकी सालिहपारा, चौकी–हरदीबाजार, जिला कोरबा छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस स्टेशन–कुसमुंडा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 1855/2019

दिनेश कुमार चौहान पिता मोहन सिंह चौहान 28 वर्ष ग्राम रेकी, लालमतियापाड़ा, चौकी, हरदीबाजार, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस स्टेशन–कुसमुंडा, जिला कोरबा छत्तीसगढ़

---- उत्तरवादी

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

अपीलार्थी हेतु (सीआरए सं.555/2019 में)		श्री अख्तर हुसैन, अधिवक्ता
अपीलार्थी हेतु (सीआरए सं.576/2019 में)		श्री आदित्य खरे, अधिवक्ता
अपीलार्थी हेतु (सीआरए सं.848/2019 में)		श्री अतुल कुमार केशरवानी, अधिवक्ता
अपीलार्थी हेतु (सीआरए सं.1855/2019 में)		श्री बसंत कैवर्त्य अधिवक्ता की ओर से श्री आदित्य खरे, अधिवक्ता
उत्तरवादी–राज्य हेतु :		श्री देवेश जी. केला, पैनल अधिवक्ता

माननीय श्रीमती. रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सी. ए. वी. निर्णय

अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश के अनुसार ,

1. तथ्यों और विधि संबंधी प्रश्नों की समानता को ध्यान में रखते हुए, और चूंकि ये सभी अपीलें एक ही अपराध से संबंधित हैं और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कटघोरा, जिला कोरबा (सी.जी.) के न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 15/2018 में दिनांक 13.03.2019 को पारित निर्णय को चुनौती देती हैं, इसलिए इन्हें एक साथ मिलाकर, समरूप रूप से सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।

2. यह सर्वविदित है कि अभियुक्त महेत्रिन बाई (ए-3) का सत्र विचारण के दौरान निधन हो गया था। जहां तक अभियुक्त सोनू दास महंत (ए-9) का संबंध है, उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर दोषमुक्त कर दिया गया है कि उनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. यह भी स्वीकृत तथ्य है कि इस न्यायालय के समक्ष लंबित दाण्डिक अपील के दौरान अभियुक्त फोटो लाल अनंत (ए-1) का निधन हो गया।इसके फलस्वरूप, उनकी ओर से दायर अपील, सीआरए संख्या 778/2019, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2025 को पारित आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय , के समक्ष पेश किए गए कुल नौ आरोपियों में से दो की मृत्यु हो चुकी है और एक को दोषमुक्त कर दिया गया है।इस प्रकार, वर्तमान में इस अपील पर विचार के लिए केवल छह आरोपी ही इस न्यायालय के समक्ष शेष हैं।

5. अपीलकर्ता - सरिता बाई अनंत (ए-2), श्रीमती रेशम बाई कुर्रे (ए-4) और धीरेन्द्र कुमार बघेल (ए-5) ने सीआरए संख्या 555/2019, अपीलकर्ता राजू दास महंत (ए-8) ने सीआरए संख्या 576/2019, अपीलकर्ता राजा @ रामाशंकर पटेल (ए-7) ने सीआरए संख्या 848/2019 और अपीलकर्ता दिनेश कुमार चौहान (ए-6) ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "सीआरपीसी") की धारा 374(2) के तहत सीआरए संख्या 1855/2019 दायर की है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कटघोरा, जिला कोरबा (सी.जी.) के न्यायालय के माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 15/2018 में दिनांक 13.03.2019 को पारित निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को निम्नानुसार दोषी ठहराया गया है और दंड पारित किया गया है:---

फोटो लाल अनंत (ए-1), सरिता बाई अनंत (ए-2), श्रीमती. रेशम बाई कुर्रे (ए-4) तथा

धीरेंद्र कुमार बघेल (ए–5)

दोषसिद्धि		दंड
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 302 के तहत		आजीवन कारावास तथा रु.500/– का जुर्माना, जुर्माने का भुगतान न करने पर, प्रत्येक अपीलार्थी को एक महीने हेतु अतिरिक्त कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 302 के तहत		आजीवन कारावास तथा रु.500 का जुर्माना, जुर्माने का भुगतान न करने पर, प्रत्येक अपीलार्थी को एक महीने हेतु अतिरिक्त कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 201 के तहत		जुर्माने का भुगतान न करने पर तीन वर्ष हेतु कठोर कारावास तथा रु.100 का जुर्माना, एक महीने हेतु अतिरिक्त कारावास।

यह निर्देश दिया गया था कि दोनों दंड को एक साथ चलाया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनेश कुमार चौहान (ए–6) तथा राजा @रामाशंकर पटेल (ए–7)

दोषसिद्धि		दंड
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 के तहत		आजीवन कारावास तथा रु.500 का जुर्माना, जुर्माने का भुगतान न करने पर, प्रत्येक अपीलार्थी को एक महीने हेतु अतिरिक्त कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 302 के तहत		आजीवन कारावास तथा रु.500 का जुर्माना, जुर्माने का भुगतान न करने पर, प्रत्येक अपीलार्थी को एक महीने हेतु अतिरिक्त कारावास।
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 201 के तहत		तीन वर्ष हेतु कठोर कारावास तथा रु.100–का जुर्माना,जुर्माने के भुगतान में चूक, प्रत्येक अपीलार्थी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास।

यह निर्देश दिया गया था कि समस्त दंड एक साथ चलेंगी।

6. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह था कि 10.07.2017 को लगभग 11:30 बजे, भिलाई बाजार गांव में, अभियुक्तों ने अपने सामान आशय के अग्रसर में तथा एक आपराधिक षड़यंत्र के तहत,विनोद कुमार अनंत की लाठी और डंडे से पीट–पीटकर जानबूझकर हत्या कर दी। इसके बाद,विधिक दंड से स्वयं को बचाने हेतु , उन्होंने मृतक के शव के साथ–साथ घटना में इस्तेमाल की गई रॉड, लाठी और मोटरसाइकिल को भी छिपा दिया और घटनास्थल पर खून के धब्बों को गोबर से ढककर साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया।

7. आरोप है कि उक्त तिथि को मृतक अपने पिता, आरोपी फोटो लाल अनंत (अब मृतक) से 2,00,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि लेने गया था, परंतु वह वापस नहीं लौटा।इसके परिणामस्वरूप, 11.07.2017 को मृतक की माता श्रीमती संतारा बाई (पीडब्लू-2) ने कुसमुंडा पुलिस स्टेशन के हरदी बाजार चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।अन्वेषण के दौरान, 24.09.2017 को आरोपी फोटो लाल का ज्ञापन बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अन्य सह-आरोपियों के साथ मृतक की हत्या करने की बात स्वीकार की।उक्त प्रकटीकरण के आधार पर, अपराध संख्या 189/2017 दर्ज किया गया और आगे की अन्वेषण की गई थी।

8. इसके बाद, मृतक का कंकाल आरोपी द्वारा बताए गए स्थान से बरामद किया गया और पंचनामा तैयार किया गया।कंकाल का शव परिक्षण किया गया और हड्डियों को जब्त कर डीएनए विश्लेषण के लिए रायपुर स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया।मौके से रॉड, लाठी और मोटरसाइकिल सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गईं।घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया और महत्वपूर्ण साक्षीयों के बयान दर्ज किए गए थे। एफएसएल से प्राप्त डीएनए रिपोर्ट ने मृतक की पहचान की पुष्टि की, तथा अन्वेषण पूरी होने पर पुलिस को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, आईपीसी) की धारा 302, 201 और 120 बी के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली।तदनुसार, 04.12.2017 को पाली स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. चूंकि यह अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 05.02.2018 के आदेश द्वारा प्रकरण को कोरबा स्थित सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र विचारण संख्या 553/2017 के रूप में पंजीकृत किया गया था।इसके बाद प्रकरण को 06.03.2018 पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

10. आरोपपत्र और संलग्न दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, अभियुक्तों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 201 के साथ धारा 34 और धारा 120 बी के तहत आरोप निर्धारित किए गए। आरोपों को अभियुक्तों को पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिन्होंने अपराध स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।

11. विचारण के दौरान, अभियुक्तों से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी दोष सिद्ध करने वाले तथ्यों से इनकार किया, अपनी निर्दोषता का दावा किया और झूठे फंसाए जाने का आरोप लगाया, साथ ही बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने से भी इनकार कर दिया।12. अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 16 साक्षी (जैसे PW-1 से PW-16) से परीक्षा की गयी और 86 दस्तावेज़ (एक्स पी/1 से एक्स पी/86) तथा 48 वस्तुएं (आर्टिकल ए/1 से आर्टिकल ए/48) पेश किये गये ।बचाव पक्ष में, अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने कोई साक्षी पेश नहीं किया गया, लेकिन दो दस्तावेज़ (एक्स डी/1 और एक्स डी/2) पेश किए गये।

13. विचारण न्यायालय ने अभिलेख प पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए, दिनांक 13.03.2019 के अपने निर्णय द्वारा, उपरोक्त अभियुक्तों को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उन्हें उपर्युक्त दंड पारित किया गया, जिसके विरुद्ध ये दाण्डिक अपीलें दायर की गई हैं।

14. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अख्तर हुसैन, श्री आदित्य खरे और श्री अतुल कुमार केशारवानी ने पुरजोर तर्क दिया है कि ये प्रकरण झूठे आरोप में फंसाए गए हैं और विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को गलत तरीके से दोषी ठहराया है।उन्होंने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष का पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और अपीलकर्ताओं को कथित अपराध से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अभियोजन पक्ष परिस्थितियों की श्रृंखला को इस तरह से स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थियों के अपराध का एकमात्र निष्कर्ष निकाला जा सके।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मृतक विनोद कुमार अनंत आरोपी फोटो लाल अनंत का सौतेला बेटा था (क्योंकि अपील लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी) तथा उक्त आरोपी की माता महेंत्रिन बाई के नाम पर भूमि अधिग्रहण के कारण कुछ क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई थी।मृतक द्वारा क्षतिपूर्ति में अपना हिस्सा मांगने जाने और आरोपी फोटो लाल अनंत द्वारा सह–आरोपी धीरेंद्र कुमार बघेल के साथ मिलकर उसे खत्म करने के लिए पेशेवर हत्यारे दिनेश कुमार चौहान और राजा उर्फ रामाशंकर पटेल को नियुक्त करने के आरोप को निराधार और ठोस साक्ष्य से रहित बताया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आरोपी फोटोलाल द्वारा कथित तौर पर ₹3.5 लाख की निकासी और आरोपी दिनेश कुमार चौहान को कथित तौर पर ₹3 लाख के भुगतान का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। इस प्रकार की निकासी या भुगतान को साबित करने के लिए कोई बैंक अभिलेख या स्वतंत्र साक्षी पेश नहीं किया गया है।इसी तरह, आरोपी धीरेन्द्र कुमार बघेल और आरोपी फोटो लाल के बीच कथित षड़यंत्र किसी भी ठोस साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है।यह भी बताया गया है कि मृतक का शव घटना के लगभग तीन महीने बाद आरोपी फोटो लाल अनंत के ज्ञापन के आधार पर बरामद किया गया था, और तब तक शव पूरी तरह से सड़ चुका था।मृतक की पहचान कथित रूप से उसके द्वारा पहने गए जूतों तथा डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से स्थापित करने की मांग की गई थी।हालाँकि, डी. एन. ए. रिपोर्ट, साथ ही एफ. एस. एल. रिपोर्ट, अभियोजन पक्ष के मामले को निर्णायक रूप से स्थापित नहीं कर सकी, क्योंकि रक्त समूह की पुष्टि नहीं की जा सकी।

16. विद्वान अधिवक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई साक्षीयों के बयान लगभग दो महीने के विलंब के बाद दर्ज किए गए थे, जिससे उनके बयान संदिग्ध हो जाते है।अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, अर्थात् ज्ञापन संबंधी बयान, जब्त की गई वस्तुएं, कथित उद्देश्य और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत अभियुक्तों का आचरण, उन्हें अपर्याप्त और विधि के अनुसार सिद्ध नहीं माना गया।यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि संदेह और अनुमान के आधार पर दर्ज की गई थी, जो विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकती है।इस बात पर जोर दिया गया कि आपराधिक षड्यंत्र के आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को स्पष्ट और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो वर्तमान प्रकरण

में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।अंत में, यह तर्क दिया गया है कि आरोपी सोनू दास महंत, जिन पर समान साक्ष्यों के आधार पर विचारण चलाया गया था, को विचारण न्यायालय ने पहले ही दोषमुक्त कर दिया है। समानता के सिद्धांत के आधार पर, अपीलकर्ताओं भी दोषमुक्त होने के योग्य थे। तदनुसार, यह निवेदन किया गया कि दोषसिद्धि और दंड के आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है और अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त होने के योग्य है।

17. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के संबंध में अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राम शरण चतुर्वेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 16 एससीसी 166, राजा खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025) 3 एससीसी 314 और अब्दुल नासर बनाम केरल राज्य और अन्य (2025 एससीसी) ऑनलाइन एससी 111 के प्रकरण में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है।**

18. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिनमें **पुलिस अधीक्षक, सीबीआई/एसआईटी बनाम नलिनी और अन्य (1999) 5 एससीसी 253, योगेश उर्फ सचिन जगदीश जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 10 एससीसी 394, एस. अरुल राजा बनाम तमिलनाडु राज्य (2010) 8 एससीसी 233, आर. शाजी बनाम केरल राज्य (2013) 14 एससीसी 266 और सोमासुंदरम उर्फ सोमू बनाम पुलिस उप आयुक्त द्वारा प्रतिनिधित्व राज्य (2016) 16 एससीसी 355 शामिल हैं, ताकि षड्यंत्र के संबंध में उनके तर्कों को पुष्ट किया जा सके।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इसके अलावा, खुले स्थान से वसूली के संबंध में अपनी तर्क को पुष्ट करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **जयकम खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) 13 एससीसी 716** के मामले में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया गया है।

20. सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट के संबंध में, उन्होंने माधव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) 17 एससीसी 600 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है।

21. संदेह के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2024) 3 एससीसी 481 मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है।

22. इसके विपरीत, राज्य/प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री देवेश जी. केला ने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि उसमें दर्ज निष्कर्ष उचित हैं, साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित हैं और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी विवरण नहीं है, फिर भी अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामला स्थापित करने में सक्षम रहा है, और इस प्रकार सिद्ध हुई परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण, सुसंगत है और केवल अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर ही इंगित करती है।अपराध का उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका था, क्योंकि मृतक विनोद

कुमार अनंत, आरोपी फोटो लाल अनंत का सौतेला पुत्र था और आरोपी फोटो लाल अनंत की माता महेत्रिन बाई के नाम पर भूमि अधिग्रहण से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि में हिस्सेदारी को लेकर विवाद था। मृतक अपना हिस्सा लेने गया था, लेकिन उसे क्षतिपूर्ति देने के बजाय, आरोपी फोटो लाल अनंत ने सह–आरोपी धीरेंद्र कुमार बघेल के साथ मिलकर दिनेश कुमार चौहान और राजा उर्फ रामाशंकर पटेल को उसकी हत्या करने के लिए नियुक्त किया था।

23. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज आरोपी फोटो लाल अनंत के ज्ञापन बयान के आधार पर, मृतक का शव उसके द्वारा बताए गए स्थान से दिपका वन में बरामद किया गया था।अभियुक्तों की सूचना पर बरामदगी एक मजबूत साक्ष्य है जो अपराध में उनकी संलिप्तता को पुष्ट करता है।छड़ी, लाठी, मोटरसाइकिल और अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी अभियोजन पक्ष के बयान की पुष्टि करती है।यह भी तर्क दिया गया है कि मृतक की पहचान विधिवत स्थापित की गई थी। यद्यपि शव सड़ी हुई अवस्था में था, फिर भी घटनास्थल से बरामद वस्तुओं के आधार पर उसकी पहचान की गई और डीएनए प्रोफाइलिंग के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई।एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट परिस्थितियों की कड़ी में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कड़ी का काम करती हैं।राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि कुछ साक्षीयों के बयान दर्ज करने में हुये विलंब, इस मामले के तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष के पक्ष में घातक नहीं है, विशेषकर तब जब मौखिक और दस्तावेजी दोनों प्रकार के समग्र साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पक्ष का समर्थन करते हैं।आरोपियों का आचरण, उनके द्वारा लगाए गए आरोप, अपराधबोध से संबंधित वस्तुओं की बरामदगी और वैज्ञानिक साक्ष्य सामूहिक रूप से उनके अपराध को संदेह से परे साबित करते हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि सह–आरोपी सोनू दास महंत की रिहाई से वर्तमान अपीलकर्ताओं को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनके विरुद्ध साक्ष्य भिन्न प्रकृति के थे, जबकि अपीलकर्ता कई मजबूत अपराधबोधकारी परिस्थितियों के माध्यम से अपराध से जुड़े हुए हैं। तदनुसार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि अपीलें खारिज कर दी जाएं विद्वान विचारण द्वारा अपीलार्थियों पर लगाए गए दोषसिद्धि तथा दंड को यथावत रखा जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क को सुना , उनके उपरोक्त प्रतिपक्षों पर विचार किया और अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

25. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता उक्त अपराध के अपराधी हैं।

26. यह अपराध कथित तौर पर 10.07.2017 को सुबह लगभग 11:30 बजे ग्राम भिलाई बाजार स्थित आरोपी फोटोलाल के घर पर हुआ था।अगले दिन, पीडब्लू 2, श्रीमती संतारा बाई द्वारा मृतक विनोद कुमार अनंत के लापता होने की सूचना दर्ज कराई गई (एक्स पी/ 2)।इसके बाद एफआईआर दिनांक 26.09.2017 को पीडब्लू 12, ग्रहण सिंह राठौर (प्रदर्श पृष्ठ/38) द्वारा दर्ज की गई थी, तथा अन्वेषण पीडब्लू 14, शरद चंद्र द्वारा की गई थी।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ताओं ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत विनोद

कुमार अनंत की हत्या लाठियों, लकड़ी के डंडों और अन्य औजारों से की और बाद में शव और अन्य साक्ष्यों का निराकरण कर दिया गया ।मृतक का पोस्टमार्टम पीडब्लू संख्या 5, डॉ. अंशुल (प्रदर्श पृष्ठ/47) द्वारा किया गया था।

27. अन्वेषण के दौरान, आरोपियों से अलग–अलग समय पर ज्ञापन संबंधी बयान दर्ज किए गए।अभियुक्त फोटो लाल अनंत से 24.09.2017 को 17:00 बजे (एक्स पी/5); दिनेश कुमार चौहान से 26.09.2017 को 08:00 बजे (एक्स पी/16); राजू दास महंत से 26.09.2017 को 08:40 बजे (एक्स पी/23); राजा उर्फ रामाशंकर पटेल से 26.09.2017 को 08:30 बजे (एक्स पी/20); और सोनू दास महंत से 27.09.2017 को 17:30 बजे (एक्स पी/52)।

28. इन ज्ञापन कथनों के आधार पर कई बरामदगी की गई, जो दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों से सिद्ध हुईं। आरोपी फोटो लाल अनंत से शव बरामद किया गया था। दिनेश कुमार चौहान से सीजी–12–एबी–4244 नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की गई (प्रदर्श पत्र/17)।राजा उर्फ रामाशंकर से लकड़ी का तेंदू गदा (प्रदर्श पत्र/21) और सीजी–12–एई–4361 नंबर की टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल (प्रदर्श पत्र/22) जब्त की गई।राजू दास महंत से एक कुल्हाड़ी, एक लोहे का फावड़ा और एक लकड़ी का डंडा बरामद किया गया (एक्स पी/24)।सूनू दास महंत से एक लकड़ी का तेंदू गदा जब्त किया गया (एक्स पी/25)। महेत्रिन बाई से एक बैंक पासबुक बरामद की गई (एक्स पी/2), और गवाह लाल सिंह कंवर से भूमि अभिलेख जब्त किए गए (एक्स पी/8)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इसके अलावा, शव की पहचान 26.09.2017 को की गई (एक्स पी/72), और शव का सुपर्दनामा उसी दिन तैयार किया गया (एक्स पी/30)।शव परीक्षण रिपोर्ट 26.05.2017 को दर्ज की गई (एक्स पी/47), जबकि एफएसएल रिपोर्ट 31.01.2018 को तैयार की गई (एक्स पी/81), और डीएनए रिपोर्ट 13.03.2019 को तैयार की गई (एक्स पी/82)।

30. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के विवाद्यक पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम शरण चतुर्वेदी (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है:–––

"27. आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का मुख्य तत्व अपराध करने का करार है।ऐसे करार को प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किया जाना चाहिए। न्यायालय को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्या अपीलकर्ता और ए–1 तथा ए–2 के बीच कोई करार हुआ था।

28. केरल राज्य बनाम पी. सुगाथन तथा ए. एन. आर., (2000) 8 एस. सी. सी. 203 के निर्णय में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है **कि करार षड्यंत्र के अपराध का मूल तत्व है, और इसे किसी न किसी भौतिक प्रमाण के माध्यम से साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना चाहिए:"**

12. .....अन्य सभी आपराधिक अपराधों की तरह, अभियोजन पक्ष को आरोपी के विरुद्ध मामले को संदेह से परे साबित करने का दायित्व निभाना होता है।

.....अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कुछ छोटे–मोटे सबूतों को आरोपी को आपराधिक षड्यंत्र के अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है.....

13. .....इस अपराध का सबसे महत्वपूर्ण तत्व दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने का करार है।आपराधिक षड्यंत्र के आरोप वाले मामले में, न्यायालय को यह जाँच करनी चाहिए कि क्या दोनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक ही उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं या उन्होंने विधि विरुद्ध उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ आए हैं।पहला मामला उन्हें षड्यंत्रकारी नहीं बनाता है, जबकि दूसरा बनाता है।षड्यंत्र के अपराध के लिए करार की किसी प्रकार की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति स्थापित करना आवश्यक है।स्पष्ट करार को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है।गैरकानूनी कृत्य से संबंधित विचारों के आदान–प्रदान के साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं...(जोर दिया गया)

29.अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए षड्यंत्र के आरोप में उसके द्वारा किए गए स्पष्ट कृत्यों या आचरण का प्रमाण होना चाहिए, जो ए–1 और ए–2 के साथ एक सामान्य योजना में सचेत और स्पष्ट सहमति को दर्शाता हो।**राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम नवजोत संधू, (2005) 11 एससीसी 600 में,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है:

"101. एक और सिद्धांत जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह यह है कि सिद्ध परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को आरोपी के अपराध का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, न कि प्रत्येक परिस्थिति के लिए अलग–अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।बेशक, प्रत्येक परिस्थिति को संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए। अंत में, षड्यंत्र से संबंधित साक्ष्यों के मूल्यांकन के संबंध में, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पक्षों के कार्य या आचरण सचेत और इतने स्पष्ट हों कि उनसे सामान्य योजना और उसके क्रियान्वयन के संबंध में उनकी सहमति का अनुमान लगाया जा सके। "(जोर दिया गया)

30.अभियोजन पक्ष की कहानी को स्वीकार करते हुए, निचली अदालत के साथ–साथ उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ता के खिलाफ मात्र संदेह के आधार पर कार्यवाही की, जिसके बारे में इस न्यायालय ने तनवीबेन पंकजकुमार दिवेटिया बनाम गुजरात राज्य, (1997) 7 एससीसी 156 में चेतावनी दी थी:

45. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि का सिद्धांत इस न्यायालय के कई निर्णयों में स्पष्ट किया गया है और यह कानून सर्वमान्य है कि प्रत्येक दोष सिद्ध करने वाली परिस्थिति को विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य द्वारा स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार सिद्ध परिस्थितियाँ घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करनी चाहिए जिससे अभियुक्त के अपराध के बारे में एकमात्र अकाट्य निष्कर्ष सुरक्षित रूप से निकाला जा सके और अपराध के विरुद्ध कोई अन्य परिकल्पना संभव न हो। इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर काफी हद तक निर्भर मामले में,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमेशा यह खतरा रहता है कि अनुमान या संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान ले सकते हैं। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि घटनाओं की श्रृंखला में विभिन्न परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई हैं और घटनाओं की ऐसी पूर्ण श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषता की उचित संभावना को खारिज किया जा सके।यह भी बताया गया है कि जब महत्वपूर्ण कड़ी टूट जाती है, तो परिस्थितियों की श्रृंखला बिखर जाती है और अन्य परिस्थितियाँ किसी भी तरह से आरोपी के अपराध को सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं कर सकतीं है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए और संदेह को कानूनी प्रमाण का स्थान लेने देने के खतरे से बचना चाहिए, क्योंकि कभी–कभी अनजाने में ही नैतिक निश्चितता और कानूनी प्रमाण के बीच का अंतर बहुत कम हो सकता है।इस न्यायालय ने यह संकेत दिया है कि "संभवतः सत्य" और "निश्चिततः सत्य" के बीच एक लंबा मानसिक अंतर है, और यही अंतर अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है।(जहरलाल दास बनाम उड़ीसा राज्य (1991) 3 एससीसी 27)"(जोर दिया गया)

31.यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्तों के बीच स्पष्ट, निश्चित और प्रत्यक्ष करार हो। हालांकि, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामलों में स्थापित सिद्धांतों के आधार पर एक निहित करार प्रकट होना चाहिए।तदनुसार, राम नारायण पोपली बनाम सी. बी. आई., (2003) 3 एस. सी. सी. 641 की बहुमत राय में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया थाः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"354. ..... षड्यंत्र के अपराध के लिए करार की किसी प्रकार की भौतिक अभिव्यक्ति स्थापित करना आवश्यक है।स्पष्ट करार को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।गैरकानूनी कृत्य में विचारों के आदान–प्रदान के संबंध में साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं...

32. इस न्यायालय द्वारा आपराधिक षड्यंत्र पर कानून के स्पष्ट प्रतिपादन को देखते हुए, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष न्यायालय को यह संतुष्ट करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता और ए–1 तथा ए–2 के बीच पहले से कोई सहमति थी। आसपास की परिस्थितियों, बयानों या अपीलकर्ता के आचरण से ऐसी किसी सहमति का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता है।साक्ष्य में अपीलकर्ता द्वारा अभियुक्तों के साथ षड़यंत्र रचने की अप्रत्यक्ष स्वीकृति तक नहीं है, अपीलकर्ता के षड़यंत्र में स्पष्ट और सचेत भागीदारी का तो कोई प्रमाण ही नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय ने मात्र संदेह को करार के प्रमाण की कानूनी आवश्यकता से प्रतिस्थापित करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। "

31. राजा खान (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–––––

"25. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, क्योंकि न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी है और न ही न्यायिक रूप से स्वीकार्य

कोई स्वीकारोक्ति बयान है।यह सुस्थापित विधि है कि जहां मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो, वहां साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि केवल सिद्ध किए जाने वाले साक्ष्य को छोड़कर बाकी सभी परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया जाए और ऐसी परिस्थितियां दर्शाएं कि यह कृत्य अपीलकर्ता-आरोपी द्वारा मानवीय संभावनाओं के आधार पर किया गया है (देखें हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1952) 2 एससीसी 71)।26. शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 में, इस न्यायालय ने पांच आवश्यक सिद्धांतों को रेखांकित किया, जिन्हें अक्सर पांच स्वर्णिम सिद्धांत कहा जाता है, जिन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा अपीलकर्ता-आरोपी के अपराध को निर्णायक रूप से स्थापित करने के लिए संतुष्ट किया जाना चाहिए:(एस. सी. सी. पी. 185, कंडिका 153)

"153. ....(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

* * *

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्, अभियुक्त के दोषी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के आधार पर उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है।

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभव परिकल्पना को खारिज कर देना चाहिए।

(5) साक्ष्यों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं के अनुसार यह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा। "

32. अब्दुल नासर (ऊपर,) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

"30. परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में साक्ष्यों का मूल्यांकन और आकलन करते समय न्यायालयों को जिन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना हम आवश्यक समझते हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i)अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के प्रत्येक गवाह की गवाही पर सावधानीपूर्वक चर्चा और विश्लेषण किया जाना चाहिए।प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी महत्वपूर्ण पहलू अनदेखा न रह जाए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ii).परिस्थितिजन्य साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जो किसी तथ्यात्मक निष्कर्ष से जुड़ने के लिए अनुमान पर निर्भर करता है।अतः, प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य से निकाले जा सकने वाले उचित निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

(iii).दोषी ठहराने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की प्रत्येक कड़ी की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रत्येक परिस्थिति व्यक्तिगत रूप से सिद्ध होती है और क्या सामूहिक रूप से लेने पर, वे एक अटूट श्रृंखला बनाती हैं जो केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप है और उसकी निर्दोषता के बिल्कुल विपरीत है।

((iv)।निर्णय में विशिष्ट साक्ष्यों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के पीछे के तर्क को विस्तार से स्पष्ट किया जाना चाहिए, और यह दर्शाया जाना चाहिए कि साक्ष्यों से निष्कर्ष तार्किक रूप से कैसे निकाला गया। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि प्रत्येक साक्ष्य किस प्रकार अपराध साबित करने में योगदान देता है।

(v).निर्णय में यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि दोषी पाया जाता है, तो वह परिस्थितियों का उचित और सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के बाद ही लिया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे किसी अन्य उचित परिकल्पना के साथ संगत हैं या नहीं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. आपराधिक षड़यंत्र से संबंधित विवाद्यक के निराकरण के बाद, अब भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120 बी को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः---

"[120 बी. आपराधिक षड्यंत्र का दंड

--(1) जो कोई भी मृत्युदंड, 2 [आजीवन कारावास] या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में भागीदार है, यदि इस संहिता में ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे अपराध को उकसाया हो।

(2) जो कोई भी उपर्युक्त दंडनीय अपराध करने के लिए रची गई आपराधिक षड़यंत्र के अलावा किसी अन्य आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। "

34. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपराधिक षड़यंत्र के अपराध को दो अलग-अलग श्रेणियों में दंडनीय बनाया गया है, अर्थात्:पहला, जहां षड़यंत्र मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि हेतु कठोर कारावास से दंडनीय गंभीर अपराध करना है, तथा दूसरे, यदि षड्यंत्र किसी अन्य अपराध को अंजाम देने के लिए किया गया हो, तो उस स्थिति में दंड अपेक्षाकृत कम होती है।

35. आपराधिक षड्यंत्र के विवाद्यक पर विचार करते हुए, **योगेश उर्फ सचिन जगदीश जोशी (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:---**

"25. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि किसी अवैध कृत्य या अवैध साधनों द्वारा कृत्य करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों की सहमति आपराधिक षड्यंत्र की अनिवार्य शर्त है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा उनके बीच हुए करार को सिद्ध करना संभव नहीं हो सकता है।फिर भी, षड्यंत्र का अस्तित्व और उसका उद्देश्य आसपास की परिस्थितियों और आरोपी के आचरण से समझा जा सकता है।परंतु दोष सिद्ध करने वाली परिस्थितियाँ घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करनी चाहिए जिससे आरोपी के अपराध के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके।यह सर्वविदित है कि षड्यंत्र का अपराध एक मूल अपराध है और किसी अपराध को करने के लिए मात्र करार करना भी दंडनीय है, भले ही अवैध करार के परिणामस्वरूप कोई अपराध न हुआ हो।"

36. एस. अरुल राजा (उपरोक्त) में, नलिनी (उपरोक्त) के मामले से निपटते हुए, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:---

"27. राज्य में पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई./एस. आई. टी. बनाम नलिनी और अन्य के माध्यम से (1999) 5 एस. सी. सी. 253 में यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

"583.(1).....आपराधिक षड्यंत्र का अपराध सामान्य कानून का अपवाद है, जहाँ केवल आशय से अपराध नहीं बनता है।इसमें अपराध करने का आशय और समान आशय वाले व्यक्तियों के साथ हाथ मिलाना शामिल है।न केवल आशय, बल्कि आशय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहमति भी होनी चाहिए, जो एक अपराध है। किसी मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सभी आरोपियों का आशय था और क्या वे अपराध करने के लिए सहमत थे।किसी भी अभियुक्त के मन में मात्र यह इच्छा होना, चाहे वह कितनी भी जघन्य क्यों न हो, कि अपराध किया जाए, षड्यंत्र का अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा... 28. इस मामले में, अपीलकर्ता की संलिप्तता साबित करने के लिए मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य आईपीसी की धारा 120-ए के तहत आपराधिक षड्यंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आपसी सहमति को ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध किया जाना चाहिए और प्रतिवादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो इसे रेखांकित करता हो।ए 1 की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए उसके बयान का उपयोग उक्त षड्यंत्र में अपीलकर्ता को फंसाने के लिए किया जा सकता है या नहीं, इस विवाद्यक पर बाद में विचार किया जाएगा।"

37. इसके अलावा **आर. शाजी (उपरोक्त)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया :

"54. आपराधिक षड्यंत्र आमतौर पर गुप्त रूप से रचा जाता है, जिसके कारण प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना कठिन होता है।इसलिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करके या आवश्यक निहितार्थ के माध्यम से अपराध को सिद्ध किया जा सकता है।हालांकि, यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपूर्ण या अस्पष्ट हो, तो अभियोजन पक्ष के लिए

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आवश्यक आपसी सहमति का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है, जिसके लिए उसे अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।इसके अतिरिक्त, षड्यंत्र का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित व्यक्ति को कार्रवाई के सभी चरणों की जानकारी हो।वास्तव में, षड्यंत्र के मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य की मात्र जानकारी भी संबंधित दंड प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, दो व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने या करवाने का समझौता दंड संहिता के तहत षड्यंत्र के अपराध की मूलभूत आवश्यकता है।(देखें: मीर नागवी अस्करी बनाम सी. बी. आई., ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 528; बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 2009 एस. सी. सप.1629; राज्य एम. पी. बनाम शीतला सहाय, ए. आई. आर. 2009 एस. सी. सप.1744; आर. वेंकटकृष्णन बनाम सी. बी. आई., ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1812; एस. अरुल राजा बनाम टी. एन. राज्य, (2010) 8 एस. सी. सी. 233; मोनिका बेदी बनाम ए. पी. राज्य, (2011) 1 एस. सी. सी. 284; तथा सुशील सूरी बनाम सी. बी. आई., ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 1713।"

38. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोमासुंदरम उर्फ सोनू (उपरोक्त)** मामले में इसी तरह के विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया है:---

"146. अब मैं आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपीलकर्ताओं के बरी होने के प्रभाव पर विचार करता हूँ। आरोपी अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 365 के साथ धारा 109, धारा 387, 302 के साथ धारा 109, धारा 347 के साथ धारा 109, धारा 364 के साथ धारा 109 और धारा 201 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब धारा 109 के तहत आरोप सिद्ध हो चुका है, तो केवल धारा 120 बी के तहत उनका दोषमुक्त होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है।" धारा 109 के विशिष्ट तत्वों के तहत लगाए गए आरोपों को निचली दोनों अदालतों ने उचित पाया है। आईपीसी की धारा 120 बी के तहत उनकी रिहाई से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकती, क्योंकि दोनों धाराओं के तहत अपराध अलग-अलग हैं।धारा 120 बी ए-1 और ए-2 के खिलाफ और अन्य आरोप अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ सिद्ध पाए गए हैं।

147. इस न्यायालय ने धारा 109 के अंतर्गत अपहरण और षड्यंत्र तथा उसकी व्याख्या पर विचार किया है और इसकी तुलना धारा 120 बी के अंतर्गत इन अपराधों से की है। न्यायालय ने यह माना है कि धारा 109 के अंतर्गत उकसाने वाले को वही दंड दिया जा सकता है जो मुख्य अपराधी को दिया जा सकता है यदि मुख्य अपराधी का कृत्य उकसाने के परिणामस्वरूप किया गया हो। धारा 120B के अंतर्गत षड्यंत्र का अपराध भिन्न है।धारा 120□ किसी ऐसे अपराध को करने का मात्र समझौता है जिसे धारा 120B के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है। इन दोनों श्रेणियों के अपराधों के लिए दंड भी काफी भिन्न हैं।धारा 109 आईपीसी केवल उकसाने के दंड से संबंधित है जिसके लिए आईपीसी में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध एक स्वतंत्र अपराध है जिसे धारा 120□ आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है जिसके लिए धारा 109 के अंतर्गत आरोप लगाना अनावश्यक और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुचित है।रंगनायकी बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक (2004) 12 एससीसी 521 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :

"10. किसी आपराधिक कृत्य को अंजाम देने का मकसद आम तौर पर अभियोजन के लिए एक कठिन क्षेत्र होता है।कोई भी व्यक्ति आम तौर पर दूसरे के मन की बात नहीं जान सकता। उद्देश्य वह भावना है जो किसी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। गंभीर अपराध करने के लिए ऐसे प्रेरक कारण का समान रूप से गंभीर होना आवश्यक नहीं है। कई हत्याएं बिना किसी ज्ञात या स्पष्ट उद्देश्य के की गई हैं। यह बहुत संभव है कि उपरोक्त प्रेरक कारक अज्ञात रहेगा।लॉर्ड चीफ जस्टिस कैंपबेल ने रेड बनाम पामर मामले में सावधानी बरतते हुए कहा [शॉर्टहैंड रिपोर्ट पृष्ठ 308, मई 1856]: "परंतु यदि कोई उद्देश्य बताया जा सकता है, तो मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य हूं कि उस उद्देश्य की पर्याप्तता का कोई महत्व नहीं है।दाण्डिक न्यायालय के अनुभव से हम जानते हैं कि इस तरह के जघन्य अपराध बहुत मामूली मकसद से किए गए हैं; न केवल द्वेष और प्रतिशोध से, बल्कि थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए और कुछ समय के लिए गंभीर कठिनाइयों से छुटकारा पाने के लिए भी।""

हालांकि, यह मानना उचित है कि प्रत्येक आपराधिक कृत्य किसी न किसी उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन यह कहना गलत है कि उद्देश्य सिद्ध हुए बिना किसी भी आपराधिक कृत्य को अपराध नहीं माना जा सकता है। आखिरकार, उद्देश्य एक मनोवैज्ञानिक घटना है।केवल इस तथ्य से कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों की उस मानसिक स्थिति को साक्ष्य में प्रस्तुत करने में विफल रहा, यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि हमलावरों के मन में ऐसी कोई मानसिक स्थिति मौजूद नहीं थी।एटली बनाम यू. पी. राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807 में यह अभिनिर्धारित किया गया थाः(ए. आई. आर. पी. 810, कंडिका 6)

"6. .....यह सत्य है, और जहाँ अपराध के लिए उद्देश्य का स्पष्ट प्रमाण है, वह अदालत के इस निष्कर्ष को अतिरिक्त समर्थन देता है कि आरोपी दोषी था, लेकिन उद्देश्य के स्पष्ट प्रमाण का अभाव जरूरी नहीं कि विपरीत निष्कर्ष की ओर ले जाता है।

कुछ मामलों में प्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से उद्देश्य स्थापित करना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य मामलों में परिस्थितियों से प्राप्त निष्कर्ष संबंधित व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति को समझने में सहायक हो सकते हैं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें आरोपी के उन मानसिक विचारों का पता लगाना संभव न हो जो उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हों।सभी मामलों में यह सिद्ध करना संभव नहीं है कि किसी विशेष परिस्थिति में आरोपी का मन कैसे कार्य कर रहा था।कभी–कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि स्थापित उद्देश्य कमजोर है। केवल यही बात अभियोजन पक्ष के विरुद्ध निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है।यदि उद्देश्य का अभाव मान भी लिया जाए, तो भी यह आरोपी के पक्ष में नहीं जाता है।इन सिद्धांतों का परीक्षण वास्तविक परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. खुले स्थान से बरामदगी और अभियुक्त के ज्ञापन से संबंधित मुद्दे पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जयकम खान (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है: ---

75. यद्यपि विचारण न्यायालय के निर्णय में विभिन्न मामलों में गंभीर दुर्बलताएं हैं, हम उक्त निर्णय के केवल एक कंडिका का उल्लेख करते हैंःउपरोक्त उल्लेखित मोमिन, जैकम, साजिद और नजरा के खून से सने कपड़ों की बरामदगी भी अपराध में उनकी संलिप्तता को साबित करती है।उपरोक्त बरामदगी से यह भी संकेत मिलता है कि हत्याओं की पूरी घटना पूर्व नियोजित थी और इसके लिए एक व्यापक रणनीति बनाई गई थी। सभी आरोपी हत्याओं को अंजाम देने से पहले मोमिन के घर पर इकट्ठा हुए थे। वे पहले से ही जानते थे कि धारदार हथियारों से हत्या करने पर खून के छींटे उनके कपड़ों पर पड़ेंगे, जिसके कारण यदि वे अपने कपड़े नहीं बदलते हैं, तो भागने के दौरान वे अपने अपराध को छिपा नहीं पाएंगे।इसीलिए उन्होंने आरोपी मोमिन के घर में अपने लिए अतिरिक्त कपड़े पहले से ही जुटा रखे थे। अपराध करने के बाद, योजना के अनुसार वे मोमिन के घर गए, कपड़े बदले और भाग गए। घटना के तीसरे दिन मोमिन के बेटों और बेटियों द्वारा घर का ताला खोलना भी इस बात का संकेत देता है कि या तो मोमिन के सभी पुत्र और पुत्रीयां घटना के समय घर पर थे और घटना के बाद आरोपियों के साथ घर से चले गए, या फिर मोमिन और नजरा के बच्चे घटना के समय घर पर मौजूद ही नहीं थे और सभी बच्चों को घटना से पहले उनके दादा–दादी के घर भेज दिया गया था।चूंकि अपराध सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, इसलिए यह अधिक संभावना है कि घटना से पहले बच्चों को उनके दादा–दादी के घर भेज दिया गया था।यदि इस संभावना को मान लिया जाए, तो घटना के बाद आरोपी नजरा की गिरफ्तारी और शेष तीन आरोपियों मोमिन, साजिद और जयकाम की गिरफ्तारी राजघाट चौराहे पर रात 2 बजे न होकर सुबह 6:30 बजे होना महत्वपूर्ण हो जाता है।इससे संकेत मिलता है कि नजरा घटना के बाद अपने बच्चों से मिलने और उन्हें घर की चाबियां सौंपने गई थी।इसके बाद, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, उसे उसी राजघाट चौराहे पर पहुंचना था, जहां शेष तीन आरोपियों को रात में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी आरोपियों ने शायद उसी चौराहे पर इकट्ठा होकर एक साथ भागने की योजना बनाई थी और इसीलिए वे रात 2 बजे तक नजरा का उसी स्थान पर इंतजार करते रहे।इस कारण से भी यह असंभव है कि यदि घटना रात लगभग 8:30 बजे हुई हो, तो तीनों आरोपी मोमिन, ज़ैकम और साजिद के पास अपराध करने के बाद बहुत दूर भागने का पर्याप्त समय हो।हालांकि, राजघाट चौराहे पर रात 2:00 बजे तक खड़े रहना यह दर्शाता है कि वे वहाँ नजरा के आने का इंतजार कर रहे थे।"

76. कम से कम कहने के लिए, हम उपरोक्त निष्कर्ष पर हैरान हैं।यह वर्णन एक कहानी के रूप में पढ़ने में रोचक है।हालांकि, सभी टिप्पणियाँ मात्र अनुमान और अटकलें हैं, जिनका कोई प्रमाणिक समर्थन नहीं है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपियों के जीवन और मृत्यु के प्रश्न पर विचार करते हुए इस मामले को इतनी लापरवाही से कैसे निराकरण किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

77. इस स्तर पर, हम स्वयं को और देश के सभी न्यायालयों को आपराधिक न्यायशास्त्र में पालन किए जाने वाले स्वर्णिम सिद्धांत की याद दिलाना चाहेंगे।इस न्यायालय ने, प्रसिद्ध न्यायाधीश एच.आर. खन्ना, न्यायमूर्ति के माध्यम से, पंजाब राज्य बनाम जागीर सिंह, बलजीत सिंह और करम सिंह (1974) 3 एससीसी 277 के मामले में यह टिप्पणी की:

"23. आपराधिक विचारण किसी परीकथा की तरह नहीं होता, जिसमें व्यक्ति अपनी कल्पना और दृष्टांतों को उड़ान देने के लिए स्वतंत्र हो।इसमें इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या विचारण में पेश किया गया आरोपी उस अपराध का दोषी है, जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। अपराध वास्तविक जीवन की एक घटना है और विभिन्न मानवीय भावनाओं के परस्पर प्रभाव का परिणाम है। अपराध करने के आरोप में किसी आरोपी के दोषी होने के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए, न्यायालय को साक्ष्यों का मूल्यांकन संभावनाओं, उनके आंतरिक मूल्य और गवाहों की मंशा के आधार पर करना होता है। अंततः प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों पर निर्भर करता है।"

यद्यपि हर तरह के उचित संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए, फिर भी अदालतों को ऐसे साक्ष्यों को खारिज नहीं करना चाहिए जो प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, ऐसे आधारों पर जो काल्पनिक हों या अनुमानों पर आधारित हों।आवश्यक समझे जाने वाले अन्य आदेश पारित करे। "

78. उच्च न्यायालय ने इस मामले से जिस तरह निपटा है, उससे हम आश्चर्यचकित हैं।कपड़ों की बरामदगी के संबंध में उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगा।

"63. यह तर्क दिया गया है कि कपड़ों की बरामदगी साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया था।यह सही है कि अभियोजन पक्ष ने बरामदगी साबित करने के लिए केवल औपचारिक गवाह पेश किया, लेकिन दूसरी ओर, आरोपी मोमिन की बेटी हिना द्वारा दी गई चाबियों से कमरे के खोले जाने के तथ्य का बचाव पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया गया, जबकि हिना को पेश करके ऐसी किसी भी बरामदगी से इनकार किया जा सकता था।"

79. यह निष्कर्ष न केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की व्याख्या करने वाले सुस्थापित कानून के विपरीत है, बल्कि यह आरोपी पर एक बोझ डालने का भी प्रयास करता है, जो तब तक नहीं हटता जब तक कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित नहीं कर दिया हो।

80. उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियाँ भी अनुमानों और अटकलों के दायरे में आती हैं: "65. एक और पहलू है जिसका उल्लेख करना आवश्यक है, अर्थात् चोटों की अनेकता और एक साथ छह व्यक्तियों की हत्या को देखते हुए, यह किसी एक हमलावर का कृत्य नहीं हो सकता है।इसलिए, तीन हमलावरों मोमिन, जयकम और साजिद की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार का हमला स्वाभाविक रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. देश दीपक कुमार विहंगम उर्फ दीपक कुमार बनाम बिहार राज्य, (2022) 7 एससीसी 721 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:---

19. इस स्तर पर धारा 120–बी आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य के तत्वों और मानक के संबंध में कानून की स्थापित स्थिति पर चर्चा करना अनिवार्य है। मोंड खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2002) 7 एससीसी 334 में, इस न्यायालय ने आपराधिक षड्यंत्र के तत्वों को स्पष्ट किया था, जो निम्नानुसार हैं:(एस. सी. सी. पी. 351, कंडिका 17)

"17..... आपराधिक षड्यंत्र के तत्व इस प्रकार बताए गए हैं:(क) एक उद्देश्य जिसे पूरा किया जाना है, (ख) उस उद्देश्य को पूरा करने के साधनों से युक्त एक योजना या युक्ति, (ग) दो या दो से अधिक अभियुक्त व्यक्तियों के बीच एक समझौता या समझ जिसके द्वारा वे समझौते में निहित साधनों या किसी भी प्रभावी साधन द्वारा उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने के लिए निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, और (घ) उस क्षेत्राधिकार में जहां कानून द्वारा एक प्रत्यक्ष कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आपराधिक षड्यंत्र का सार गैरकानूनी संयोजन है और आमतौर पर अपराध संयोजन के बनने पर ही पूर्ण हो जाता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. आपराधिक षड्यंत्र को साबित करने में अभियोजन पक्ष को जिन प्रमाण मानकों को पूरा करना होता है, उन पर विस्तार से बताते हुए, इस न्यायालय ने केरल राज्य बनाम पी. सुगथन, (2000) 8 एससीसी 203 में निम्नलिखित निर्णय दिया:(एस. सी. सी. पी. 211. कंडिका 12)

"12.हम इस तथ्य से अवगत हैं कि आपराधिक षड्यंत्र के प्रत्यक्ष स्वतंत्र साक्ष्य आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं और इसका अस्तित्व अनुमान पर आधारित होता है।निष्कर्ष आमतौर पर साजिशकर्ताओं के बीच साझा उद्देश्य की पूर्ति में किए गए कार्यों से निकाले जाते हैं।इस न्यायालय ने वी.सी. शुक्ला बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) (1980) 2 एससीसी 665 मामले में यह माना कि आपराधिक षड्यंत्र को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य होना आवश्यक है जिससे यह पता चले कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने का करार हुआ था।षड्यंत्रकारियों के बीच अपराध करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेने हेतु विचारों की एकरूपता होनी चाहिए और जहां परिस्थितियों से षड्यंत्र का तथ्य निकाला जाना हो, वहां अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि परिस्थितियां दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपराध करने के समझौते का निर्णायक या अकाट्य निष्कर्ष उत्पन्न करती हैं।अन्य सभी आपराधिक मामलों की तरह, अभियोजन पक्ष को आरोपी के विरुद्ध मामले को संदेह से परे साबित करने का दायित्व निभाना होता है। किसी मामले की परिस्थितियाँ, जब उन्हें समग्र रूप से देखा जाए, तो यह दर्शाती हैं कि षड्यंत्रकर्ताओं के बीच किसी अवैध कृत्य को अंजाम देने या किसी ऐसे कृत्य को अंजाम देने के उद्देश्य से सहमति थी जो अवैध नहीं है, लेकिन अवैध साधनों द्वारा किया गया था।अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कुछ छोटे–मोटे सबूतों को आरोपी को आपराधिक साजिश के अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

यह प्रदर्शित करना होगा कि अपनाए गए सभी साधन और किए गए सभी अवैध कृत्य रची गई साजिश के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे।निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, वे कथित षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए किए गए अपराध के वास्तविक कृत्य से पहले की होनी चाहिए।

21. इस न्यायालय ने सीबीआई बनाम के. नारायण राव (2012) 9 एससीसी 512 में अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी. पी. 530, कंडिका 24)

"24.आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए आवश्यक तत्व यह हैं कि षड्यंत्र रचने वाले व्यक्तियों के बीच एक समझौता होना चाहिए और यह समझौता किसी अवैध कार्य को करने या अवैध साधनों द्वारा ऐसे कार्य को करने के लिए होना चाहिए जो स्वयं अवैध न हो।दूसरे शब्दों में, आपराधिक षड्यंत्र का सार किसी अवैध कार्य को करने का करार है और ऐसे समझौते को प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य या दोनों के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, और यह सामान्य अनुभव है कि षड्यंत्र को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं।तदनुसार, आरोपी की संलिप्तता का निर्णय करने के लिए घटना से पहले और बाद में सिद्ध हुई परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक है।यदि कुछ कृत्य सिद्ध भी हो जाते हैं, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि वे कथित षड्यंत्र में शामिल आरोपियों के बीच हुए करार के अनुसार किए गए थे। सिद्ध परिस्थितियों के आधार पर दोष के संबंध में निष्कर्ष तभी निकाला जा सकता है जब ऐसी परिस्थितियों का कोई अन्य उचित स्पष्टीकरण संभव न हो।दूसरे शब्दों में, एक षड़यंत्र के अपराध को केवल संदेह तथा अनुमानों या निष्कर्षों पर स्थापित नहीं माना जा सकता है जो ठोस तथा स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. मोहम्मद नौशाद बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार),(2024) 12 एससीसी 494 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया हैः---

89. षड्यंत्र एक प्रमुख आरोप होने के कारण, हम अभियुक्त व्यक्तियों के बीच षड्यंत्र के मुद्दे पर कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश), (1988) 3 एससीसी 609 (तीन–न्यायाधीशों की पीठ) के निर्णय पर भरोसा करते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने कहाः(एस. सी. सी. पीपी. 731–35, कंडिका 271–77 तथा280)

"271. बलबीर सिंह के विरुद्ध अन्य मामलों पर विचार करने से पहले, आईपीसी की धारा 120–ए और 120–बी के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र की अवधारणा पर विचार करना उपयोगी होगा। इन प्रावधानों ने भारत में षड्यंत्र कानून को अंग्रेजी कानून के अनुरूप बना दिया है, क्योंकि किसी दंडनीय अपराध को अंजाम देने के लिए किए गए षड्यंत्र में प्रत्यक्ष कृत्य अनिवार्य नहीं है।इस मामले पर अंग्रेजी कानून सुस्थापित है।"रसेल ऑन क्राइम (12 वां संस्करण, खंड 1,पृष्ठ 202) से निम्नलिखित अंश को ध्यान में रखना उपयोगी हो सकता है:"षड्यंत्र के अपराध का सार न तो कृत्य करने में, न ही षड्यंत्र के उद्देश्य को पूरा करने में, न ही ऐसा करने का प्रयास करने में, और न ही दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाने में निहित है, बल्कि पक्षों के बीच योजना

या करार के निर्माण में निहित है।करार आवश्यक है।केवल योजना की जानकारी या उस पर चर्चा मात्र पर्याप्त नहीं है।"

272. ग्लानविल विलियम्स ने आपराधिक कानून (द्वितीय संस्करण,पृष्ठ 382) में इस प्रस्ताव को एक उदाहरण सहित समझाया है:"

यह प्रश्न आयोवा के एक मामले में उठा, लेकिन इस पर साजिश के संदर्भ में चर्चा की गई, न कि सहभागिता के संदर्भ में।डी, जिसका पी के विरुद्ध शिकायत थी, ने ई से कहा कि यदि वह पी को कोड़े मारेगा तो कोई उसका जुर्माना भर देगा।ई ने उत्तर दिया कि वह नहीं चाहता कि कोई उसका जुर्माना भरे, क्योंकि पी के विरुद्ध उसकी अपनी शिकायत थी और वह उसे पहले अवसर पर ही कोड़े मारेगा।ई कोड़े मारे गए पी. डी. को षड़यंत्र से दोषमुक्त कर दिया गया क्योंकि 'कॉन्सर्ट ऑफ एक्शन' हेतु कोई करार नहीं था, 'सहयोग' हेतु कोई करार नहीं था।"

273. आर.वी. मर्फी (1837) 8 कार एंड पी 297 में जूरी के समक्ष मामले का सारांश प्रस्तुत करते हुए न्यायमूर्ति कोलरिज ने प्रासंगिक रूप से कहा:(ईआर पृष्ठ 508)

".....मैं आपको यह बताने के लिए बाध्य हूं कि हालांकि सामान्य डिजाइन चार्ज की जड़ है, लेकिन यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि ये दोनों पक्ष आपस में मिले और वास्तव में एक साझा योजना बनाने और उसे साझा साधनों से पूरा करने के लिए सहमत हुए, और इस प्रकार उसे अंजाम दिया। यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई मामलों में, सबसे स्पष्ट रूप से स्थापित साजिशों में भी, ऐसी किसी भी बात को साबित करने का कोई साधन नहीं होता है, और न ही कानून और न ही सामान्य ज्ञान यह अपेक्षा करता है कि इसे साबित किया जाए।यदि आप पाते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों ने अपने कृत्यों द्वारा एक ही उद्देश्य की पूर्ति की, अक्सर एक ही साधनों का उपयोग करते हुए, एक व्यक्ति ने दूसरे कार्य का एक भाग पूरा किया, ताकि वे अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, तो आप यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक षड्यंत्र में शामिल थे।आपको स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा, 'क्या उनकी यह साझा योजना थी, और क्या उन्होंने इसे इन साझा साधनों से पूरा किया – जबकि यह योजना विधि विरुद्ध थी?' "

274. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि षड्यंत्र के अपराध का सबसे महत्वपूर्ण तत्व दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी अवैध कार्य को करने का करार है।अवैध कार्य करार के अनुसरण में किया गया हो या न भी किया गया हो, लेकिन स्वयं करार ही एक अपराध है और दंडनीय है।आईपीसी की धारा 120–ए और 120–बी का संदर्भ इन पहलुओं को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है।दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी अवैध कार्य को करने या अवैध साधनों से वैध कार्य करने के लिए समझौता करना ही षड्यंत्र का मूल तत्व है।

275. आम तौर पर, षड्यंत्र गुप्त रूप से रचा जाता है और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना कठिन हो सकता है।अभियोजन पक्ष अक्सर विभिन्न पक्षों के कृत्यों के साक्ष्यों पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकालता है कि वे उनके साझा आशय के अनुरूप किए गए थे।अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भी अधिक भरोसा करता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है।प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से षड्यंत्र निस्संदेह सिद्ध किया जा सकता है।लेकिन न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि क्या दोनों व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक ही उद्देश्य की पूर्ति कर रहेहैं या वे गैरकानूनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ आए हैं।पहला उन्हें षड्यंत्रकारी नहीं बनाता, लेकिन दूसरा उन्हें षड्यंत्रकारी बनाता है।हालांकि, यह आवश्यक है कि षड्यंत्र के अपराध के लिए किसी प्रकार की सहमति की भौतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता हो।। हालांकि, स्पष्ट सहमति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। न ही दो व्यक्तियों का वास्तविक मिलना आवश्यक है। न ही संचार के वास्तविक शब्दों को साबित करना आवश्यक हैविधि विरुद्ध योजना को साझा करने वाले विचारों के प्रसारण के बारे में सबूत पर्याप्त हो सकते हैं। न्यूज़ीलैंड के कैंटरबरी विश्वविद्यालय के गेराल्ड ऑर्चर्ड इस प्रस्ताव की सीमित प्रकृति की व्याख्या करते हैं:[1974 आपराधिक विधि पुनर्विलोकन 297, पी।299]

"यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध के लिए करार की कोई भौतिक अभिव्यक्ति आवश्यक है, फिर भी इस प्रस्ताव की सीमित प्रकृति को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।कानून के अनुसार समझौते के लिए कोई विशेष रूप होना आवश्यक नहीं है और समझौते की जानकारी शब्दों या आचरण द्वारा भी दी जा सकती है। इस प्रकार, यह कहा गया है कि यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि पक्षकार वास्तव में एक साथ आए और गैरकानूनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए शर्तों पर सहमत हुए; किसी स्पष्ट मौखिक समझौते की आवश्यकता नहीं है, यह पर्याप्त है कि साजिशकर्ताओं के बीच इस बात पर एक मौन सहमति थी कि क्या किया जाना चाहिए।""

276. मैं इस राय से सहमत हूँ, लेकिन यह कहना चाहूँगा कि पक्षों के सापेक्ष कार्य या आचरण विवेकपूर्ण और स्पष्ट होने चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे इस बात पर सहमत थे कि क्या किया जाना चाहिए। यह सहमति अप्रासंगिक तथ्यों के समूह से नहीं निकाली जा सकती जिन्हें चतुराई से इस प्रकार व्यवस्थित किया गया हो कि वे सुसंगत प्रतीत हों।हानिरहित, निर्दोष या अनजाने में घटित घटनाओं और प्रसंगों को न्यायिक निर्णय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।इसलिए हमें पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए।

277. यह सुझाव दिया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के आलोक में, भारत में षड्यंत्र के प्रमाण में साक्ष्य की प्रासंगिकता अंग्रेजी कानून की तुलना में व्यापक है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 ने अभिकरण के सिद्धांत को लागू किया और यदि उसमें निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं, तो एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य सह–षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध स्वीकार्य होते हैं।धारा 10 में लिखा है:"

"**10. सामान्य योजना के संदर्भ में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातें।–जहाँ** यदि यह मानने का उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई अपराध या दंडनीय अपराध करने की साजिश रची है, तो ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा उनके साझा इरादे के संदर्भ में कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात, उस समय के बाद जब उनमें से किसी एक ने पहली बार ऐसा इरादा किया था, साजिश में शामिल माने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध एक प्रासंगिक तथ्य है, न केवल साजिश के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से बल्कि यह दिखाने के उद्देश्य से भी कि ऐसा कोई व्यक्ति उसमें भागीदार था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

* * *

280. मिर्ज़ा अकबर मामले में प्रिवी काउंसिल का निर्णय [1940 एससीसी ऑनलाइन पीसी 27,] एआईआर पृष्ठ 180 पर दिया गया है।इस निर्णय का उल्लेख सरदुल सिंह कावीशर बनाम बॉम्बे राज्य [(1957 एससीसी ऑनलाइन एससी 15) एससीआर पृष्ठ 193 पर किया गया है, जहाँ न्यायमूर्ति जगन्नाथदास ने कहा: (एससीसी ऑनलाइन एससी कंडिका 29)

29.साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत षड्यंत्र के मामलों में साक्ष्य की स्वीकार्यता की सीमाएँ प्रिवी काउंसिल द्वारा मिर्ज़ा अकबर बनाम सम्राट (ए. आई. आर. 1940 पी. सी. 176,180) मामले में आधिकारिक रूप से निर्धारित की गई हैं।उस मामले में, प्रिवी काउंसिल के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 की व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार की जानी चाहिए कि किया गया, लिखा गया या बोला गया कोई भी कार्य षड्यंत्र को अंजाम देने के उद्देश्य से किया गया था और षड्यंत्र के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है।उन्होंने यह भी कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत 'ऐसे किसी भी व्यक्ति (अर्थात षड्यंत्रकारियों) द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई किसी भी बात' का साक्ष्य 'उनके सामान्य आशय' के संदर्भ में होना चाहिए।लेकिन माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त वाक्यांश की व्यापकता के बावजूद, उपरोक्त सुप्रसिद्ध सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, इसके शब्दों की व्यापक व्याख्या नहीं की जा सकती है।"(जोर दिया गया) इसके अलावा, स्टेट बनाम नलिनी (1999) 5 एससीसी 253 (तीन-न्यायाधीशों की पीठ) में, इस न्यायालय ने षड्यंत्र के कानून को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया, यद्यपि वे प्रकृति में व्यापक हैं, तथा अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 515-18 पैराग्राफ 581-83) "581. यह सच है कि धारा 10 में निहित प्रावधान सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य के नियम से विचलन है।धारा 10 के तहत साक्ष्य की स्वीकार्यता पर दो आपत्तियां उठाई जा सकती हैं: (1) जिस षड्यंत्रकारी के साक्ष्य को सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध स्वीकार किया जाना है, उसका सह-षड्यंत्रकारी द्वारा न्यायालय में सामना या जिरह नहीं की जाती है, और (2) अभियोजन पक्ष केवल यह सिद्ध करता है कि यह मानने का उचित आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध करने की षड्यंत्र रची है, और इससे सह-षड्यंत्रकारी को फंसाने के लिए एजेंसी संबंध का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत ही, इस आधार पर कि यह संबंध मौजूद है, एक षड्यंत्रकारी का बयान सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध स्वीकार्य है।अभियोजन पक्ष को निस्संदेह धारा 10 के लागू होने के लिए साजिश के अस्तित्व के संबंध में स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, लेकिन उसे इसे उचित संदेह से परे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।आपराधिक षडयंत्र एक करार में साझेदारी है और प्रत्येक साजिश में एक सामान्य उद्देश्य, जो कि एक अपराध या दंडनीय अपराध है, के निष्पादन के लिए एक संयुक्त या पारस्परिक एजेंसी होती है।जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी षड्यंत्र में शामिल होते हैं, तो उस समझौते के तहत उनमें से किसी एक द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कानून की दृष्टि से, उन दोनों का संयुक्त कार्य माना जाता है और वे उसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं।इसका अर्थ यह है कि षड्यंत्रकारियों में से किसी के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा अपने साझा इरादे के निष्पादन में या उसके संदर्भ में कही, लिखी या की गई कोई भी बात, उन दोनों द्वारा कही, की या लिखी गई मानी जाती है।हालांकि, उपर्युक्त षड्यंत्र की समाप्ति के बाद षड्यंत्रकारी द्वारा किए गए कृत्यों के लिए कोई भी षड्यंत्रकारी उत्तरदायी नहीं होता है।न्यायालय को किसी सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध किसी षड्यंत्रकारी के बयान को आसानी से स्वीकार करने से बचना चाहिए। धारा 10 खतरनाक आपराधिक गिरोहों से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत एक सह-आरोपी के बयान को दूसरे के विरुद्ध प्रयोग करने से रोकने वाला सामान्य साक्ष्य नियम, उस अधिनियम की धारा 10 के मद्देनजर षड्यंत्र के वाद में लागू नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि अदालत को किसी सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध किसी षड्यंत्रकारी के बयान को आसानी से स्वीकार करने से बचना चाहिए, तो हमारा तात्पर्य यह है कि अदालत सुरक्षा के लिहाज से कुछ पुष्टिकरण की तलाश करती है।यह कानून का नियम नहीं है, बल्कि कानून से संबंधित विवेक का नियम है।सब कुछ कहने के बाद, अंततः न्यायालय को साक्ष्यों के मूल्यांकन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। 582. भगवानदास केशवानी बनाम राजस्थान राज्य [(1974) 4 एससीसी 611, एससीसी पृष्ठ 613 पर] इस न्यायालय ने कहा कि षड्यंत्र के मामलों में, षड्यंत्र के अनुसरण में सह-षड्यंत्रकारियों के कृत्यों और कथनों से बेहतर साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं।583. षड्यंत्र कानून को नियंत्रित करने वाले कुछ व्यापक सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, हालांकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सारांश सिद्धांतों का संपूर्ण विवरण नहीं हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1).धारा 120-ए आईपीसी के तहत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध तब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं या अवैध साधनों द्वारा किसी कानूनी कार्य को करवाने के लिए सहमत होते हैं।जब यह अवैध साधनों द्वारा किया गया कोई कानूनी कार्य होता है तो प्रत्यक्ष कृत्य आवश्यक होता है।आपराधिक षड्यंत्र का अपराध सामान्य कानून का अपवाद है जहां केवल इरादा ही अपराध नहीं बनता है।यह किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने का आशय है।केवल आशय ही नहीं, बल्कि इरादे को अंजाम देने के लिए सहमति भी होनी चाहिए, जो एक अपराध है। किसी मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या सभी आरोपियों का इरादा था और क्या वे अपराध करने के लिए सहमत थे।षड्यंत्र के अपराध के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा कि कुछ आरोपियों ने केवल अपराध करने की इच्छा रखी हो, चाहे वह कितनी भी भयावह क्यों न हो।

(2.).षड्यंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति के बाद किए गए कृत्य यह साबित कर सकते हैं कि कोई विशेष आरोपी षड्यंत्र का हिस्सा था।षड्यंत्र का उद्देश्य प्राप्त हो जाने के बाद, कोई भी बाद का कृत्य, चाहे वह गैरकानूनी ही क्यों न हो, आरोपी को षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनाता, जैसे कि किसी भगोड़े को शरण देना।

(3).षड्यंत्र निजी तौर पर या गुप्त रूप से रचा जाता है।प्रत्यक्ष साक्ष्य से षड्यंत्र को साबित करना लगभग असंभव है।आमतौर पर, षड्यंत्र के अस्तित्व और उसके उद्देश्यों का अनुमान परिस्थितियों और आरोपी के आचरण से लगाया जाता है।

(4).उदाहरण के लिए, षड्यंत्रकारियों को एक श्रृंखला में शामिल किया जा सकता है – ए, बी को शामिल करता है, बी, सी को शामिल करता है, और इसी तरह आगे भी; और यदि वे ऐसा इरादा रखते हैं और सहमत होते हैं, तो वे सभी एक ही षड्यंत्र के सदस्य होंगे, भले ही प्रत्येक सदस्य केवल उस व्यक्ति को जानता हो जिसने उसे शामिल किया है और उस व्यक्ति को जिसे वह शामिल करता है।इसमें एक तरह की अनौपचारिक नामांकन प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें केंद्र में बैठा एक व्यक्ति नामांकन करता है और बाकी सभी सदस्य एक–दूसरे से अपरिचित होते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। ये सैद्धांतिक बातें हैं और व्यवहार में यह बताना मुश्किल हो सकता है कि किसी विशेष मामले में कौन सी षडयंत्र किस श्रेणी में आती है।हालांकि, यह आपस में ओवरलैप भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपसी हित का होना आवश्यक है।व्यक्ति एक ही षडयंत्र के सदस्य हो सकते हैं, भले हीउनमें से प्रत्येक अन्य कई लोगों की पहचान से अनजान हो, जिनकी भूमिकाएँ अलग–अलग हो सकती हैं षडयंत्र के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी षडयंत्रकर्ताओं को एक ही या सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सहमत होना पड़े।

(5).जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी षड्यंत्रकारी अपराध को अंजाम देने के लिए सहमत होते हैं, तो चाहे उन्होंने इसके लिए कोई योजना बनाई हो या उस पर विचार किया हो, और भले ही उनमें से किसी ने भी अपने साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई कदम न उठाया हो, फिर भी इस समझौते में शामिल प्रत्येक व्यक्ति अपराध करता है।इस प्रकार, दो षड्यंत्रकारी होने चाहिए और एक से अधिक भी हो सकते हैं। षड्यंत्र के आरोप को साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इच्छित अपराध किया गया हो या नहीं। यदि अपराध किया गया है, तो इससे अभियोजन पक्ष को षड्यंत्र के आरोप को साबित करने में और मदद मिल सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6.).यह आवश्यक नहीं है कि सभी षड्यंत्रकारी एक ही समय में साझा उद्देश्य पर सहमत हों। वे निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति से पहले किसी भी समय अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ जुड़ सकते हैं, और सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं।प्रत्येक षड्यंत्रकारी की क्या भूमिका होगी, यह सभी को ज्ञात नहीं हो सकता है, और न ही यह कि कोई षड्यंत्रकारी कब षड्यंत्र में शामिल हुआ और कब उसने इसे छोड़ा।

(7).षड्यंत्र का आरोप अभियुक्तों के लिए प्रतिकूल हो सकता है क्योंकि इससे उन्हें संयुक्त मुकदमे का सामना करना पड़ता है और न्यायालय प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध सभी साक्ष्यों पर विचार कर सकता है। अभियोजन पक्ष को न केवल यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि प्रत्येक अभियुक्त को षड्यंत्र के उद्देश्य की जानकारी थी, बल्कि करार की जानकारी भी थी।षड्यंत्र के आरोप में न्यायालय को अभियुक्तों के साथ अन्याय होने के खतरे से सावधान रहना चाहिए।कुछ लोगों के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने से सभी को दोषी ठहराया जा सकता है, जिससे बचना चाहिए।षड्यंत्र के साक्ष्यों के माध्यम से, जो किसी अन्य मूल अपराध के विचारण में स्वीकार्य नहीं होते, अभियोजन पक्ष अभियुक्तों को न केवल स्वयं षड्यंत्र में, बल्कि कथित षड्यंत्रकारियों के मूल अपराध में भी फंसाने का प्रयास करता है।

षड्यंत्र के प्रत्येक सदस्य के सटीक योगदान का पता लगाना हमेशा कठिन होता है, लेकिन षड्यंत्र के अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य होना आवश्यक है।जैसा कि न्यायाधीश लर्न्ड हैंड ने कहा, "यह अंतर आज महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अभियोजक उन सभी को षड्यंत्र के दायरे में लाने की कोशिश करते हैं जो किसी भी हद तक मुख्य अपराधियों से जुड़े हुए हैं।"

(8.) जैसा कि ऊपर कहा गया है, षड्यंत्र के अपराध का सार या मूल तत्व गैरकानूनी समझौता है, न कि उसका क्रियान्वयन।आपराधिक षड्यंत्र का अपराध तब भी पूर्ण हो जाता है, भले ही उद्देश्य की पूर्ति के साधनों के बारे में कोई समझौता न हुआ हो।यह विधि विरुद्ध करार ही षड्यंत्र के अपराध का मुख्य आधार है। वह विधि विरुद्ध करार जो षड्यंत्र का रूप ले सकता है, औपचारिक या स्पष्ट होना आवश्यक नहीं है, बल्कि परिस्थितियों, विशेष रूप से षड्यंत्रकारियों के कथनों, कार्यों और आचरण से अंतर्निहित और अनुमानित हो सकता है।यह करार सभी पक्षों द्वारा एक ही समय में किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि उनके षड्यंत्र में शामिल होने के प्रमाण स्वरूप क्रमिक कार्यों द्वारा भी किया जा सकता है।

(9.) यह कहा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र अपराध में साझेदारी है, और प्रत्येक षड्यंत्र में एक सामान्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए संयुक्त या पारस्परिक सहयोग होता है।इस प्रकार, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी षड्यंत्र में शामिल होते हैं, तो उनमें से किसी के द्वारा करार के अनुसार किया गया कोई भी कार्य, कानून की दृष्टि से, उनमें से प्रत्येक का कार्य है और वे इसके लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। इसका अर्थ यह है कि सामान्य उद्देश्य के निष्पादन या संवर्धन में किसी भी षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई, लिखी गई या की गई प्रत्येक बात को उनमें से प्रत्येक द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई माना जाता है।और यह संयुक्त उत्तरदायित्व न केवल मूल समझौते के अनुसार किसी भी षड्यंत्रकारी द्वारा किए गए कार्यों तक सीमित है, बल्कि मूल उद्देश्य से संबंधित और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य कार्यों तक भी सीमित है। हालाँकि, षड्यंत्र की समाप्ति के बाद किसी सह-षड्यंत्रकारी द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई षड्यंत्रकारी उत्तरदायी नहीं होता है।किसी षड्यंत्र में किसी नए सदस्य के शामिल होने से न तो कोई नया षड्यंत्र बनता है और न ही इससे अन्य षड्यंत्रकारियों की स्थिति बदलती है, और केवल इस तथ्य से कि षड्यंत्रकारी व्यक्तिगत रूप से या समूहों में एक सामान्य लक्ष्य के लिए अलग-अलग कार्य करते हैं, कोई षड्यंत्र कई अलग-अलग षड्यंत्रों में विभाजित नहीं हो जाता है।

(10).कोई व्यक्ति शब्दों या कार्यों द्वारा किसी षड्यंत्र में शामिल हो सकता है। हालाँकि, किसी षड्यंत्र के लिए आपराधिक उत्तरदायित्व के लिए केवल निष्क्रिय रवैया ही पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति षड्यंत्र की जानकारी रखते हुए कोई प्रत्यक्ष कृत्य करता है, वह दोषी है। और जो व्यक्ति चुपचाप षड्यंत्र के उद्देश्य से सहमत होता है और अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर षड्यंत्र को अंजाम देता है, यहाँ तक कि दूसरों को षड्यंत्र को अंजाम देते हुए देखता रहता है, वह भी दोषी है, भले ही उसका अपराध में सक्रिय रूप से भाग लेने का कोई आशय न हो।"(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

91.अंत में, एशर सिंह बनाम ए. पी. राज्य, (2004) 11 एस. सी. सी. 585, (दो-न्यायाधीशों की पीठ) में, इस न्यायालय ने कहाः(एससीसी पृष्ठ 607, कंडिका 38-39)

"38.....किसी मामले की परिस्थितियाँ, जब उन्हें उनके मूल स्वरूप में एक साथ लिया जाता है, तो यह संकेत देना चाहिए कि साजिशकर्ताओं के बीच किसी अवैध कार्य को करने या किसी ऐसे कार्य को करने के इच्छित उद्देश्य के लिए विचारों की सहमति थी जो अवैध साधनों द्वारा अवैध नहीं है।अभियोजन पक्ष जिन कुछ तथ्यों पर निर्भर करता है, उन्हें आपराधिक षड्यंत्र के अपराध से आरोपी को जोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।यह सिद्ध करना होगा कि अपनाए गए सभी साधन और किए गए सभी अवैध कृत्य रचे गए षड्यंत्र के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थे।निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया जाता है, वे कथित षड्यंत्र की पूर्ति के लिए किए गए वास्तविक अपराध से पहले की होनी चाहिए।

39. सार्वजनिक दृष्टि से खुले किसी ऊंचे स्थान पर ज़ोर-ज़ोर से की गई चर्चा की तुलना में गोपनीयता और एकांत किसी षड्यंत्र की अधिक विशेषताएँ हैं।षड्यंत्र के प्रमाण में प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होते हैं; षड्यंत्र का अपराध प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों से सिद्ध किया जा सकता है। आपराधिक षड्यंत्र के गठन की तारीख, षड्यंत्र के गठन में भाग लेने वाले व्यक्तियों, साजिशकर्ताओं द्वारा साजिश के उद्देश्य के रूप में निर्धारित लक्ष्य और साजिश के उद्देश्य को अंजाम देने के तरीके के बारे में हमेशा पुख्ता सबूत देना संभव नहीं होता है; यह सब अनिवार्य रूप से अनुमान का विषय है।(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. इसके अलावा माधव (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय अभिनिर्धारित किया गया :-

"29. इस तथ्य के अलावा कि जिन साक्षीयों की उपस्थिति में कथित तौर पर हथियारों को जब्त किया गया था, वे मुकर गए थे, एक और बात भी थी।यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उन हथियारों में खून के धब्बे मौजूद थे, जो मृतक के खून से मेल खाते थे।दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने इस गलत धारणा पर कार्यवाही की कि केवल प्रदर्श पी-25 (एफएसएल रिपोर्ट) के अनुसार, पुलिस द्वारा जब्त किए गए चाकू और लाठियों में मानव रक्त के धब्बे होने के कारण आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद थे।अभियोजन पक्ष एफएसएल रिपोर्ट या किसी अन्य माध्यम से यह साबित नहीं कर पाया है कि चाकू और लाठियों में मौजूद खून के धब्बे मृतक के ही थे।

30. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस पहलू पर विचारों में मतभेद है।राघव प्रपन्ना त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1963 एस. सी 74) मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बहुमत से यह माना कि, "...केवल रक्त से सनी मिट्टी की उपस्थिति से यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि वह मिट्टी मानव रक्त से सनी थी और वह मानव रक्त पीड़ितों का था..."।कांसा बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1987) 3

एस. सी. सी. 480 के मामले में, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को इस आधार पर बरी कर दिया कि यद्यपि सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में अपीलकर्ता के कब्जे से बरामद कमीज और धोती पर मानव रक्त के धब्बे पाए गए थे, फिर भी मृतक के रक्त से उनका संबंध साबित करने वाला कोई सबूत नहीं है।सुरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1989) अनुपूरक(2) एससीसी 21 में, अपराध करने के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए चाकू पर पाए गए रक्त के धब्बे मानव रक्त के सिद्ध हुए थे।लेकिन इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के इस सिद्धांत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चाकू पर पाए गए रक्त के धब्बे मृतक के रक्त समूह के समान नहीं थे। रघुनाथ, रामकिशन और अन्य बनामहरियाणा राज्य, (2003) 1 एससीसी 398 में इस न्यायालय ने माना कि रक्त का धब्बा, यद्यपि मानव रक्त का है, यह साबित करने के लिए निर्णायक सबूत नहीं है कि यह मृतक के रक्त समूह का है।सत्तातिया बनाम महाराष्ट्र राज्य (2008) 3 एससीसी 210 के मामले में, इस न्यायालय ने अपराध में प्रयुक्त वस्तु की बरामदगी से संबंधित साक्ष्य की विश्वसनीयता को काफी हद तक कमतर पाया, क्योंकि रक्त के धब्बे, हालांकि मानव निर्मित पाए गए थे, मृतक के रक्त से नहीं जोड़े जा सके। 31. इसके विपरीत, इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य (1999) 3 एससीसी 507 के मामले में कहा कि कई बार सीरोलॉजिस्ट रक्त के स्रोत का पता लगाने में विफल हो सकता है, या तो इसलिए कि धब्बा अपर्याप्त है या रक्त संबंधी परिवर्तनों और प्लाज्मा के जमने के कारण।राघव प्रपन्ना त्रिपाठी (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के निर्णय का हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने तेजा राम (उपरोक्त) मामले में यह माना कि ऐसा नहीं है कि रक्त के स्रोत का पता लगाने में विफलता के सभी मामलों में हथियार की बरामदगी से उत्पन्न परिस्थितियाँ महत्वहीन हो जाएँगी।इस न्यायालय ने तेजा राम (उपरोक्त) मामले में संकेत दिया कि, "...आपराधिक न्यायालय का प्रयास काल्पनिक संदेहों की खोज करना नहीं होना चाहिए..." और संदेह उचित आयाम के होने चाहिए, जिन्हें न्यायिक रूप से विवेकशील मन कुछ वस्तुनिष्ठता के साथ स्वीकार करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. तेजा राम (उपरोक्त) के निर्णय का अनुसरण गुर सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2001) 2 एससीसी 205 और प्रभु दयाल बनाम राजस्थान राज्य, (2018) 8 एससीसी 127 में किया गया।

33. आर. शाजी बनाम केरल राज्य, (2013) 14 एससीसी 266 में, इस न्यायालय ने प्रभु बाबाजी नवले बनाम बॉम्बे राज्य, एआईआर 1956 एससी 51 से लेकर राघव प्रपन्ना त्रिपाठी (उपरोक्त); तेजा राम (उपरोक्त), गुर सिंह (उपरोक्त); जॉन पांडियन बनाम राज्य, (2010) 14 एससीसी 129; और सुनील क्लिफोर्ड डेनियल बनाम पंजाब राज्य, (2012) 11 एससीसी 205 सहित लगभग सभी पूर्व निर्णयों पर ध्यान दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक बार जब आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के अनुसरण में बरामदगी की जाती है, तो रक्त समूहों का मिलान या गैर-मिलान महत्वहीन हो जाता है।

34. इसलिए, जैसा कि इस न्यायालय ने बलवान सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2019) 7 एससीसी 781 में बताया है, ऐसा कोई निश्चित सूत्र नहीं हो सकता है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा, या

साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि रक्त समूह मेल खाते हैं।परंतु न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा को वसूली तथा मानव रक्त की उत्पत्ति दोनों के बारे में संतुष्ट होना चाहिए।"

43. राया नायकर (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–––

"18. यह सर्वमान्य विधि है कि संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, उचित संदेह से परे प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है ।किसी आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो।किसी आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उचित संदेह से परे उसका दोष सिद्ध न हो जाए।"

44. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों का उल्लेख करने के बाद, अब हम इन मामलों के प्रमुख साक्षीयों के बयानों की अन्वेषण करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

45. पीडब्लू 1, रामकुमारी अनंत ने बयान दिया कि वह मृतक विनोद कुमार अनंत की पत्नी हैं।वह आरोपी फोटो लाल अनंत को अपने ससुर के रूप में जानती थीं और सरिता बाई, मेहात्रिन बाई और रेशम बाई को भी जानती थीं, जो क्रमशः उनकी मौसी, दादी और मौसी हैं।वह अन्य सह–आरोपियों को नहीं जानती थीं।उसने बताया कि उसके पति को आरोपी फोटो लाल अनंत, सरिता बाई, महेत्रिन बाई और रेशम बाई ने उमेदिभाथा बुलाया था ताकि वह एसईसीएल द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का अपना हिस्सा ले सके। उसका पति अपनी प्लैटिना बाइक से घर गया लेकिन वापस नहीं लौटा।पूरे दिन उसने उसे फोन नहीं किया, जिससे वह चिंतित हो गई।पीडब्लू–1 ने उसकी सास संतरा बाई को पूछताछ के लिए भेजा, लेकिन आरोपियों ने उसे यह कहकर गुमराह किया कि विनोद अगले दिन बैंक जाएगा और अपनी अनुपस्थिति के झूठे कारण बताए। जब उसका पति रात तक नहीं लौटा, तो उसने बार–बार उससे और अपने रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है।अगली सुबह, आरोपी उसके घर आए और झूठा दावा किया कि विनोद बैंक चला गया है।रामकुमारी अनंत और उनकी सास ने हरदी बाजार पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।उन्होंने आगे बताया कि ग्रामीणों के साथ दो–तीन दिन तक खोजबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि फोटो लाल अनंत ने बैंक से 3.5 लाख रुपये निकाले थे। लगभग तीन महीने बाद पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि उनके पति की हत्या कर दी गई है। उन्हें बताया गया कि परिवार के सदस्यों ने पीट–पीटकर उनकी हत्या कर दी और उनके शव को एक बोरी में डालकर दिपका के जंगल में दफना दिया गया।उसने शव बरामदगी की कार्यवाही के दौरान शव की पहचान की, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया।

46. प्रतिपरीक्षा में, राजकुमारी अनंत (गवाह–1) ने घटना वाले दिन अपने पति और आरोपी के बीच हुई बातचीत के बारे में अपनी अनभिज्ञता को दोहराया गया।उसने कहा कि जब उसके पति उमेदिभाथा गए थे तब वह घर पर थी और उसे नहीं पता कि आरोपी ने उससे क्या कहा था।उन्होंने पुष्टि की कि उसकी सास ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और बताया था कि विवाह के बाद वह आरोपी फोटो लाल अनंत के घर केवल एक बार गई थी।उन्हें फोटो लाल अनंत द्वारा पुलिस को दी गई किसी भी धमकी या बयान की जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें आरोपी धीरेंद्र की संलिप्तता का पता था।उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पति कभी–कभी शराब पीते थे, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें पता था कि घटना वाले दिन उन्होंने शराब पी थी या नहीं।उन्होंने अपने पति और उनके परिवार के बीच किसी भी तरह के झगड़े या विवाद को नहीं देखा, और न ही उन्हें किसी राजनीतिक या संगठनात्मक विवाद की जानकारी थी जिसमें उनके पति शामिल रहे हों।उन्होंने पुष्टि की कि उनके ससुर के पास अन्य संपत्ति थी और वे उनकी सास को मिली क्षतिपूर्ति उनके पति को देने के इच्छुक नहीं थे।पीडब्लू 1 ने स्पष्ट किया कि उसने स्वयं अपने पति के लापता होने को नहीं देखा, न ही उसने फोटो लाल अनंत के घर पर घटी घटनाओं को देखा। उसने कहा कि उसकी जानकारी मुख्य रूप से उसकी सास या ग्रामीणों द्वारा बताई गई बातों पर आधारित है। उसने यह भी पुष्टि की कि वह अपने पुलिस बयान में दर्ज कुछ विवरणों की व्याख्या नहीं कर सकती है।

47. पीडब्लू 2, श्रीमती संतारा बाई ने कहा कि वह मृतक विनोद कुमार अनंत को जानती थीं, जो उनका पुत्र था, और अदालत में उपस्थित आरोपी, जिनमें फोटो लाल अनंत भी शामिल है, उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं।उसने बयान दिया है कि 10.07.2017 को, उनके पुत्र विनोद कुमार अनंत को आरोपी फोटो लाल अनंत के घर पर महेत्रिन बाई, रेशम बाई और सरिता बाई के साथ एसईसीएल भूमि मुआवजे के रूप में ₹2,00,000/– का हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था।विनोद कुमार अनंत सुबह लगभग 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल से उमेंडीभंथा के लिए रवाना हुए, लेकिन घर नहीं लौटे। शाम को वे आरोपी के घर गए, जहाँ फोटो लाल अनंत, महेत्रिन बाई, रेशम बाई और सरिता बाई मौजूद थीं। विनोद के बारे में पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि महेत्रिन बाई की खराब तबीयत के कारण विनोद कुमार अनंत घर लौट आए हैं।वह घर लौट आई, लेकिन विनोद कुमार अनंत रात 9 बजे तक नहीं लौटा। तब वह लक्ष्मी बाई के साथ फिर से आरोपी के घर गई, जहाँ दरवाजा बंद था। जब उनसे पूछा गया कि वे सब एक साथ क्यों बैठे हैं, तो उन्होंने बताया कि कमरे में एक सांप घुस आया था। उन्होंने आगे बयान दिया कि अगली सुबह 4 बजे, फोटो लाल अनंत, महेत्रिन बाई, रेशम बाई और सरिता बाई उनके घर आए।इसके बाद, उन्होंने गांव की सभा बुलाई और हरदी बाजार पुलिस स्टेशन में गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराई (एक्स पी/2)।आरोपी फोटो लाल अनंत को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसने विनोद कुमार अनंत की हत्या में खुद को और सह–आरोपियों को दोषी ठहराते हुए बयान दिए।उसने स्वीकार किया कि विनोद कुमार अनंत के सिर पर चोट की गई थी, महेत्रिन बाई, सरिता बाई और रेशम बाई ने खून साफ किया था, और शव को एक बोरी में डालकर कुछ समय के लिए रखा गया था और बाद में कोराई वन में दफना दिया गया था। पी डब्लू–2 पुलिस और आरोपी फोटो लाल अनंत के साथ दफन स्थल पर गई, जहाँ उसने अपने बेटे के शव की पहचान की।एक पंचनामा (जांच रिपोर्ट) तैयार की गई, और उसने शव की पहचान उसके कपड़ों और जूतों से की।उन्होंने अपने पुत्र के रक्त के नमूने को डीएनए परीक्षण के लिए एकत्र करने की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सहमति भी दी (एक्स पी/ 3) और माहेत्रिन बाई के घर की तलाशी के दौरान वे उपस्थित थीं, जिसका दस्तावेजीकरण तलाशी पंचनामा (एक्स पी/ 4) में किया गया है।

48. प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू 2, श्रीमती संतारा बाई ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने पुत्र विनोद कुमार अनंत की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और यह सच नहीं है कि उन्होंने लिखित रिपोर्ट (एक्स पी/ 2) प्रस्तुत नहीं की थी।उन्होंने बताया कि उन्होंने चौथी कक्षा तक पढ़ाई की है और रिपोर्ट स्वयं तैयार की है। उन्हें पुलिस को बयान देने की सही तारीखें याद नहीं थीं, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि बयान अलग–अलग दिनों में दिए गए थे, एक ही बार में नहीं।उन्होंने न्यायालय में बढ़ा–चढ़ाकर बोलने या झूठी गवाही देने के आरोपों का खंडन किया था।उन्होंने कहा कि माहेत्रिन बाई के घर की तलाशी के दौरान, जिसमें कमरे, छत, पानी का गड्ढा और अन्य क्षेत्र शामिल थे, वे मौजूद थीं, और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनकी उपस्थिति में कोई तलाशी पंचनामा तैयार किया गया था।उन्होंने पुष्टि की कि फोटो लाल अनंत ने उनकी उपस्थिति में बयान दिए थे, और उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बयान दर्ज नहीं किए गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि जब विनोद कुमार अनंत उमेंडीभाथा गए थे, तब वे उनके साथ नहीं थीं, और उन्हें उनकी गतिविधियों की सटीक जानकारी नहीं थी।उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने आरोपियों को एक कमरे में साथ बैठे देखा था और सांप वाली घटना की सूचना दी थी, हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह उनके पुलिस बयान में दर्ज किया गया था या नहीं।उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने पुलिस के सामने इन घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।उसने ग्राम सभा में भाग लेने, हरदी बाज़ार पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने और पुलिस द्वारा की गई तलाशी में सहयोग करने की पुष्टि की। उसने कोराई जंगल से बरामद अपने बेटे के शव की पहचान की और उसके कपड़े और जूते ज़ब्त होते हुए देखने की पुष्टि की, लेकिन उसे उन वस्तुओं का ब्रांड या नंबर नहीं पता था। उसने फोटो लाल अनंत और धीरेंद्र के बीच हत्या के संबंध में हुई किसी भी बातचीत की जानकारी होने से इनकार किया और हत्या के बदले पैसों के लेन–देन को देखने से भी इनकार किया। उसने कहा कि उसने पुलिस को सूचना देने और सहायता करने में सच्चाई का पालन किया और सभी कार्य स्वेच्छा से और तथ्यात्मक रूप से किए गए थे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. इसी प्रकार, पीडब्लू– 3 अनिल पटले ने बयान दिया है कि घटना 10.07.2017 को भिलाई बाजार और उमेदीभंथा के बीच घटी थी, और विनोद कुमार अनंत की माता संतारा बाई ने बताया था कि उनका बेटा अपनी नानी महेत्रिन बाई के घर गया था और वापस नहीं लौटा था।उन्होंने बयान दिया कि 24.09.2017 को वह, गोरेलाल पटले, मंगलूरम, कैलाश और अन्य लोगों के साथ हरदी बाजार पुलिस चौकी गए, जहां उनकी उपस्थिति में आरोपी फोटोलाल अनंत का बयान दर्ज किया गया।फोटोलाल ने विनोद कुमार अनंत की हत्या के लिए राजू पटेल और दिनेश कुमार चौहान को सुपारी देने की बात स्वीकार की। बयान का ज्ञापन एक्स पी/ 5 के रूप में तैयार किया गया, जिस पर पीडब्लू 3 के हस्ताक्षर हैं।इसी तरह, सरिता बाई से पूछताछ की गई तथा उन्होंने विनोद कुमार अनंत को मारने के लिए किसी को काम पर रखने में

अपनी संलिप्तता स्वीकार की, हालांकि उन्होंने उस व्यक्ति के नाम का खुलासा नहीं किया।उन्होंने आगे कहा कि संतारा बाई द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद, एक ग्राम सभा आयोजित की गई जिसमें वह आरोपी फोटो लाल अनंत, सरिता बाई, रेशम बाई और महेत्रिन बाई सहित 40–50 ग्रामीणों के साथ उपस्थित थे। उस सभा में हत्या के संदेह पर कोई चर्चा नहीं हुई।उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने पुलिस को फोटो लाल अनंत, सरिता बाई और महेत्रिन बाई के घरों की तलाशी लेते हुए देखा था और तलाशी पंचनामा (एक्स पी/4) तैयार किया गया था।उन्होंने फोटो लाल अनंत के घर का स्थल नक्शा (एक्स पी/6) तैयार होते हुए और महेत्रिन बाई से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक (एक्स पी/ 7) जब्त होते हुए भी देखा था।

50. प्रतिपरीक्षा में, अनिल पटले (पीडब्लू–3) ने बताया कि वह उस समय उपस्थित थे जब पुलिस ने एसईसीएल के लाल सिंह से भूमि अधिग्रहण दस्तावेज जब्त किए, जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ 8) तैयार किया और जब आरोपी फोटो लाल अनंत, सरिता बाई, महेत्रिन बाई और रेशम बाई को गिरफ्तार किया गया (एक्स पी/9 –एक्स पी/12)।उसने गिरफ्तारी ज्ञापन, तलाशी पंचनामा (एक्स पी/15) और स्थल योजना (एक्स पी/6) पर हस्ताक्षर करने और महेतरिन बाई की बैंक पासबुक (एक्स पी/7) की ज़ब्ती का साक्षी होने की पुष्टि की।उसने बयान दिया कि फोटो लाल ने उसकी उपस्थिति में राजू पटेल और दिनेश कुमार चौहान को विनोद कुमार अनंत की हत्या का ठेका देने की बात स्वीकार की और हत्या का पूरा ब्यौरा दिया, जिसमें विनोद के शव को बोरी में ले जाना और सरिता बाई और महेतरिन बाई द्वारा खून साफ करना शामिल था। उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के अगले दिन संतारा बाई द्वारा बुलाई गई ग्राम सभा में उपस्थित होने की पुष्टि की और बताया कि आरोपी भी वहाँ मौजूद थे।उन्होंने कहा कि उन्होंने 24.09.2017 को पुलिस स्टेशन में अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और यह भी बताया कि स्थल योजना और ज्ञापन (एक्स पी/ 5, एक्स पी/ 6 और एक्स पी/ 15) पुलिस प्रभारी ग्रहण सिंह राठौर द्वारा तैयार किए गए थे। उन्होंने उन सभी आरोपों का खंडन किया कि पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की, उनकी उपस्थिति में पंचनामा या स्थल योजना तैयार नहीं की, या उन्हें उन दस्तावेजों की जानकारी नहीं थी जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे।उन्होंने यह भी पुष्टि की कि फोटो लाल के बयान उनकी उपस्थिति में सही ढंग से दर्ज किए गए थे, और उन्हें कोटवार द्वारा मौखिक रूप से पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का सटीक समय याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि सभी कार्यवाही, ज़ब्ती और गिरफ्तारियां उनकी उपस्थिति में हुईं।

51. पीडब्लू–4, गोरेलाल पाटले ने बयान दिया कि वह आरोपी फोटो लाल अनंत, महेंत्रिन बाई, सरिता बाई, रेशम बाई तथा न्यायालय में मौजूद अन्य अभियुक्तों को पहचानता है तथा विनोद कुमार अनंत को जानता है, जो मृतक है।10.07.2017 को, विनोद अपनी दादी महेत्रिन बाई के घर जाने के पश्चात् लापता हो गया था। उनकी माता संतरा बाई ने पीडब्लू 4 को बताया कि विनोद कुमार अनंत वापस नहीं लौटे हैं, और ग्रामीणों ने पुलिस में मामला दर्ज कराने का सुझाव दिया, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीडब्लू 4 ने बताया कि महेत्रिन बाई को एसईसीएल भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त 28 लाख रुपये के बंटवारे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को लेकर फोटो लाल अनंत और विनोद कुमार अनंत के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था।24.09.2017 को,पीडब्लू 4 और अन्य ग्रामीणों को हरदी बाजार चौकी पर बुलाया गया, जहां आरोपी फोटो लाल अनंत ने पीडब्लू 4 की उपस्थिति में पुलिस को दिए अपने बयान में स्वीकार किया कि उसने राजा पटेल और दिनेश कुमार चौहान के माध्यम से अन्य सहयोगियों की मदद से विनोद कुमार अनंत की हत्या करवाई थी। उसने विनोद की पिटाई, खून साफ करने और उसके शव को उसके घर के पीछे छिपाने का भी विवरण दिया था। सरिता बाई ने इस बयान की पुष्टि की।इसके बाद, आरोपी के मार्गदर्शन में, पीडब्लू 4 पुलिस के साथ कोराई जंगल गया, जहां विनोद का शव बरामद कर उसकी पहचान की गई। उसकी उपस्थिति में, पुलिस ने एसईसीएल भूमि के कागजात (ए/1 से ए/36, प्रदर्शनी पृष्ठ 8), महेत्रिन बाई की बैंक पासबुक (ए/37, प्रदर्शनी पृष्ठ 7), दिनेश कुमार चौहान (एक्स पी/ 17) और राजा पटेल (एक्स पी/22) से प्राप्त मोटरसाइकिलें, लाठियां, और अपराध में इस्तेमाल किया गया रैंप और फावड़ा (एक्स पी/ 21, एक्स पी/24) सहित विभिन्न वस्तुएं और दस्तावेज जब्त किए।उन्होंने आगे पुष्टि की कि वे 32 आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान उपस्थित थे और उन्होंने संबंधित गिरफ्तारी ज्ञापनों (एक्स पी/9 – एक्स पी/13, एक्स पी/26) पर हस्ताक्षर किए थे।उन्होंने पुष्टि की कि सभी बरामदगी, ज़ब्ती और बयान उनकी उपस्थिति में लिए गए थे और उन्होंने विनोद के शव और बरामद वस्तुओं की सही पहचान की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

52. प्रतिपरीक्षा में, गोरेलाल पटले (पीडब्लू–4) ने बताया कि चाय के बाद उनकी मुलाकात संतारा बाई से अदालत परिसर में हुई थी और उन्होंने पुष्टि की कि विनोद के लापता होने के बाद, ग्रामीणों और महिलाओं ने एसपी और कलेक्टर कार्यालय से संपर्क किया था क्योंकि शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।उन्होंने 24–27 सितंबर 2017 के बीच कई बार हरदी बाजार पुलिस स्टेशन और 29 सितंबर 2017 को दिपका पुलिस स्टेशन जाने की पुष्टि की, जिसमें विनोद के शव की बरामदगी के लिए पुलिस के साथ कोराई जंगल जाना भी शामिल था।पीडब्लू–4 ने राजू दास महंत, दिनेश कुमार चौहान और राजा पटेल सहित आरोपियों को पहचाना और कार्यवाही के दौरान उनकी पहचान की पुष्टि की।उन्होंने बताया कि उन्होंने सरिता बाई और धीरेंद्र से पूछताछ देखी और पुष्टि की कि उनके सामने बयान दर्ज किए गए थे, हालांकि वे पुलिस द्वारा लिखवाए गए थे और उन्हें पूरे पढ़कर नहीं सुनाए गए थे।उन्हें जब्त की गई मोटरसाइकिलों, फावड़े और लाठियों के सभी विवरण या कुछ पुलिस बयानों की सटीक सामग्री याद नहीं थी, लेकिन उन्होंने महेत्रिन बाई के एसईसीएल कागजात और पासबुक की जब्ती की पुष्टि की।पीडब्लू 4 ने बताया कि फोटो लाल अनंत और अन्य आरोपियों के बीच उनकी अनुपस्थिति में हुई बातचीत की उन्हें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी, और उन्होंने गवाही देने या आरोपियों के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन प्राप्त करने से इनकार किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पटवारी द्वारा नजरी का नक्शा तैयार करते समय उन्होंने फोटो लाल अनंत को नहीं देखा था।

53. अन्वेषण अधिकारी, पीडब्लू 12, ग्रहण सिंह राठौर ने अपने बयान में कहा है कि 11.07.2017 को संतरा बाई ने अपने लापता पुत्र विनोद कुमार अनंत के बारे में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो अपने पिता और नानी

के घर गया था और वापस नहीं लौटा (एक्स पी/2)।लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई (डायरी संख्या 25/11.07.2017, ईशान संख्या 22/17, एक्स पी/40), और सभी पुलिस स्टेशनों को वायरलेस अलर्ट भेजे गए (एक्स पी/4)।अन्वेषण के दौरान, संतरा बाई ने बार–बार शिकायत की कि विनोद कुमार अनंत की हत्या फोटोलाल अनंत, सरिता बाई और अन्य लोगों ने की थी।24.09.2017 को फोटोलाल अनंत को भिलाई बाजार के पास से पकड़ा गया और धारा 27 के तहत अपने ज्ञापन बयान में उसने कबूल किया कि उसने धीरेंद्र और चार अन्य साथियों के साथ मिलकर 3 लाख रुपये के लिए अपने बेटे की हत्या करवाई थी (एक्स पी/5)।इसी के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 120 बी और 34 के तहत एफ. आई. आर. संख्या 16/17 दर्ज की गई (एक्स पी/43, 43 सी), और गवाहों की उपस्थिति में फोटोलाल, सरिता बाई, महेतरिन बाई, रेशम बाई और धीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया (एक्स पी/9–13; एक्स पी/44 और P/45)।घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया (एक्स पी/6)। इसके बाद, दिनेश कुमार चौहान, राजा उर्फ रामाशंकर, राजू दास महत और सोनू दास महंत को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बयान गवाहों की उपस्थिति में दर्ज किए गए (एक्स पी//16, पी/20, पी/23, पी/52)।26.09.2017 को, कोराई जंगल में, उनके बयानों के अनुसार एक गड्ढा खोदा गया, और विनोद का शव बरामद कर उसकी पहचान की गई (एक्स पी/28, पी/29, पी//35, पी//37)। अन्वेषण के दौरान, अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार और मोटरसाइकिलें आरोपियों से जब्त की गईं (एक्स पी/7, पी//19, पी//22, पी//24, पी//25, व/54), और परिवार के सदस्यों को गिरफ्तारी और जब्ती के नोटिस जारी किए गए एक्स पी/49, पी//51, पी//53)।शव परीक्षण फॉर्म सीएचसी दीपका (एक्स पी/47, पी/48) को भेजे गए थे।अन्वेषण ने हत्या की षड़यंत्र में समस्त अभियुक्तों की संलिप्तता तथा साक्ष्यो की बरामदगी की पुष्टि की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

54. प्रतिपरीक्षा के दौरान, अन्वेषण अधिकारी ग्रहण सिंह राठौर (पीडब्लू–12) ने बताया कि आरोपी फोटो लाल अनंत को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, और उसके बयान के आधार पर धीरेंद्र, सरिता बाई, दिनेश और राजा पटेल को आरोपी बनाया गया था।24.09.2017 को, सरिता बाई और धीरेंद्र सतनामी को महेतरिन बाई और रेशम बाई के साथ उसी रात गिरफ्तार किया गया था।उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि उन्होंने सरिता बाई और धीरेंद्र से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ नहीं की, फिर भी फोटोलाल के बयान से साजिश में उनकी संलिप्तता सिद्ध हो गई, जिसमें 3 लाख रुपये के हत्या के अनुबंध और अपराध को छुपाने में उनकी भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया था।सरिता बाई और धीरेंद्र से कोई भी वस्तु जब्त नहीं की गई।धीरेंद्र, फोटोलाल के बहनोई का दामाद है।मामला गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट (एक्स पी/2) से शुरू हुआ, और फोटोलाल अनंत, सरिता बाई, महेतरिन बाई और रेशम बाई के साक्ष्यों ने विनोद कुमार अनंत की हत्या की पुष्टि की।उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, पंचनामा (एक्स पी/4) तैयार किया और गवाहों की उपस्थिति में सभी आरोपियों के बयान दर्ज किए।अपराध में प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं (एक्स पी/ 7, एक्स पी/ 19, एक्स पी/ 21–एक्स पी/25)।दिनेश, राजा, राजू और सोनू दास को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके परिवारों को नोटिस जारी किए गए।उन्होंने 3 लाख रुपये के लेन–देन से संबंधित बैंक पत्राचार और सीसीटीवी

फुटेज की भी जांच की, लेकिन समय बीत जाने के कारण विनोद के कमरे को सील नहीं किया। सभी कार्यवाही, बयान और जब्ती के साक्षी की निगरानी में की गई और कोई भी सबूत गढ़ा नहीं गया।

55. पीडब्लू 15, डॉ. अंशुल लाल ने बताया कि वे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दिपका स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2016 से नवंबर 2017 तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। 26.09.2017 को लगभग दोपहर 3:00 बजे, मृतक बिनोद अनंत (उम्र लगभग 30 वर्ष, फोटो लाल अनंत के पुत्र) का शव, हरदी बाजार पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल मारुत महेंद्र जगत (संख्या 197) द्वारा आवश्यक पोस्टमार्टम आवेदन के साथ, उनके समक्ष पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। जांच करने पर, डॉ. अंशुल लाल ने पाया कि शव अत्यधिक सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ गए थे।शरीर इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि हड्डियाँ दिखने लगी थीं, मृतक के चेहरे के भाव पूरी तरह विकृत हो चुके थे और शरीर पहचान से परे था।उन्होंने पाया कि मौजूद हड्डियाँ एक वयस्क पुरुष की प्रतीत होती हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया था, और सड़न की स्थिति के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि मृत्यु पोस्टमार्टम से लगभग दो से तीन महीने पहले हुई थी।

56. बाहरी रूप से देखने पर, शरीर सामान्य कद–काठी का था।खोपड़ी की हड्डियाँ दिखाई दे रही थीं, और डॉ. अंशुल लाल ने दाहिनी टिबिया हड्डी को निकालकर सील करने और आगे की जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) भेजने की सलाह दी।जांच के समय, मृतक ने बनियान और काले जूते पहने हुए थे, जिन्हें सील करके कांस्टेबल को सौंप दिया गया।हड्डियों की विस्तृत परिक्षण करने पर, शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं देखे गए।डॉ. अंशुल लाल ने राय दी कि शरीर के अत्यधिक सड़ जाने के कारण मृत्यु का सटीक कारण निर्धारित नहीं किया जा सका।हालांकि, उन्होंने अनुमान लगाया कि मृत्यु पोस्टमार्टम से लगभग दो से तीन महीने पहले हुई थी।इस संबंध में उनके द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्स पी/ 47 है। इसके अलावा, 07.11.2017 को, डॉ. अंशुल लाल ने हरदी बाजार पुलिस स्टेशन से प्राप्त एक क्यूरी आवेदन की जांच की, जिसके साथ एक लाठी और रॉड (एक्स पी/ 72) भी थी। जांच करने पर, उन्होंने अपनी राय दी कि संभवतः उक्त लाठी और रॉड से लगी चोटों के कारण मृतक की मृत्यु हुई हो सकती है।हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि शरीर के सड़ जाने के कारण मृत्यु के सटीक कारण का निश्चित रूप से पता लगाना संभव नहीं था।उनकी राय क्यूरी रिपोर्ट, एक्स पी/ 72 में दर्ज है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

57. संक्षेप में, डॉ. अंशुल लाल ने विनोद कुमार अनंत के शरीर के अत्यधिक सड़ जाने, पोस्टमार्टम से मृत्यु के सटीक कारण का पता न लगा पाने और अपनी पेशेवर राय की पुष्टि की कि लाठी और रॉड से मृत्यु हो सकती है, जैसा कि क्यूरी रिपोर्ट में दर्ज है।

58. प्रतिपरीक्षा में, डॉ. अंशुल लाल (पीडब्लू–15) ने कहा कि उनके समक्ष प्रस्तुत शव की पहचान करना संभव नहीं था, हालांकि डीएनए परीक्षण से पहचान की पुष्टि हो सकती थी।शरीर पर कीड़े स्वाभाविक रूप से मौजूद थे, पुलिस द्वारा नहीं लाए गए थे।वह शव की आयु निश्चित रूप से निर्धारित नहीं कर सका, लेकिन

उसने पुष्टि की कि यह एक वयस्क पुरुष का शव था।शव पर ताज़ी खोदी गई मिट्टी के समान अवशेष मिले, और रक्त का नमूना लेना संभव न होने के कारण नहीं लिया गया।प्रस्तुत लाठी और छड़ सीलबंद नहीं थे, और छड़ ठोस थी।उसने इस बात से सहमति जताई कि छड़ से प्रहार करने पर हड्डी में चोट लग सकती है।

59. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के कानून को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, न्यायालय निम्नलिखित का अवलोकन करता है:

(क) परिस्थितिजन्य साक्ष्य:अभियोजन पक्ष का मामलामुख्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों को उजागर किया गया है, जिनमें अभियुक्त का कथित उद्देश्य, कथित इकबालिया बयान और विभिन्न वस्तुओं की बरामदगी शामिल हैं, न्यायालय का मानना है कि परिस्थितियों की श्रृंखला न तो पूर्ण है और न ही पूरी तरह से दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अभियोजन पक्ष के विवरण में महत्वपूर्ण कमियां हैं:

ख) कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अपीलकर्ताओं को अपराध के वास्तविक क्रियान्वयन से नहीं जोड़ता है।

ग) अभियुक्तों के कई ज्ञापन बयान और गवाहों के बयानों में विसंगतियां हैं, जो कथित स्वीकारोक्तियों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घ) परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत साक्ष्य, अभियुक्त के अपराध के अलावा अन्य सभी संभावित परिकल्पनाओं को खारिज नहीं करता है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर मामलों में एक आवश्यक शर्त है।

ड) इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की समग्र रूप से जांच करने पर, यह अपीलकर्ताओं के अपराध को निर्णायक रूप से सिद्ध करने वाली घटनाओं की एक सुसंगत, अटूट श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहता है।(ख) जब्ती तथा वसूली:यद्यपि अन्वेषण के दौरान कुछ बरामदगी की गई, लेकिन न्यायालय ने कई कमियों को नोट किया है:

• कुछ बरामदगी, जिनमें छड़ें, लाठियां, मोटरसाइकिलें और दस्तावेज शामिल हैं, कथित घटना के काफी समय बाद की गई थीं, जिससे उनकी उत्पत्ति और साक्ष्य मूल्य पर संदेह पैदा होता है।

• बरामद वस्तुओं की पहचान में खामियां और विसंगतियां हैं।

• बरामदगी करने में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का लगातार पालन नहीं किया गया, जिससे ऐसी सामग्रियों का साक्ष्य महत्व कमजोर हो जाता है।

• शव के अत्यधिक सड़ जाने के कारण पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हो सका,

जिससे विशिष्ट चोटों की पहचान संभव नहीं हो सकी।

• अभियोजन पक्ष द्वारा डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट सहित वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भरोसा किया गया है, लेकिन ये साक्ष्य मृतक और आरोपी के बीच स्वतंत्र रूप से ऐसा संबंध स्थापित नहीं करते हैं जिससे सबूत का भार सिद्ध हो सके।

• इस प्रकार, जब्ती और बरामदगी का साक्ष्य मूल्य सीमित है और यह स्वतंत्र रूप से अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि का समर्थन नहीं कर सकता है।

(ग) अन्वेषण में विसंगतियां :न्यायालय ने प्रक्रिया और अन्वेषण में पाये गये कुछ उल्लेखनीय कमियों पर भी ध्यान दिया है:

• कई प्रमुख साक्षीयों के बयान दर्ज करने में काफी देरी हुई, जिससे उनके कथन की विश्वसनीयता कम हो जाती है।

• कुछ आरोपियों के बीच कथित वित्तीय लेन–देन और षड़यंत्र जैसे महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य तत्वों की पुष्टि स्वतंत्र दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्यों से नहीं हुई।

• कथित भुगतानों या संविदा के सत्यापन सहित कुछ अन्वेषण संबंधी चरण या तो अपूर्ण थे या अपर्याप्त रूप से दस्तावेजित थे, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर हो गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) सह–आरोपी का दोषमुक्त होना:आरोपी सोनू दासमहंत, जिन पर समान साक्ष्यों के आधार पर विचारण चलाया गया था, को विचारण न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है वर्तमान अपीलकर्ताओं को अपराध से जोड़ने वाले ठोस, स्वतंत्र साक्ष्यों के अभाव में, समानता का सिद्धांत अपीलकर्ताओं के पक्ष में जाता है, जो उनके दोषमुक्त होने के दावे का समर्थन करता है।

60. दोनों पक्षों के तर्क पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, इस न्यायालय का यह मत है कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, गंभीर खामियों से ग्रस्त है।

61. प्रथम, अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन्हें मुख्य रूप से आरोपी फोटो लाल अनंत के ज्ञापन वक्तव्य के आधार पर फंसाना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि वक्तव्य का केवल वही भाग साक्ष्य में स्वीकार्य है जो किसी तथ्य की खोज की ओर ले जाता है। अभियोजन पक्ष और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ज्ञापन के अस्वीकार्य भागों पर भरोसा करना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था।

62. द्वितीय, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुई है। संबंधित तिथि को आरोपी फोटो लाल अनंत के घर पर सभी अपीलकर्ताओं की उपस्थिति सिद्ध नहीं हुई है। विचारण न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय के अनुच्छेद 49 में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अभियोजन पक्ष यह

सिद्ध करने में विफल रहा है कि हत्या आरोपी फोटो लाल अनंत के घर के अंदर हुई थी। हथियारों की कथित बरामदगी भी अपराध से संबंधित नहीं है, क्योंकि एफएसएल रिपोर्ट इस बात की पुष्टि नहीं करती कि रक्त के धब्बे मानव निर्मित थे, और चिकित्सा साक्ष्य इस संबंध में निर्णायक नहीं है कि मृत्यु हत्या थी या नहीं।इस प्रकार, परिस्थितियों की श्रृंखला में आवश्यक कड़ी गायब है।

63. तृतीय, शव की खोज का श्रेय अपीलकर्ताओं को नहीं दिया जा सकता है। अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पुलिस को अपीलकर्ताओं दिनेश कुमार चौहान, राजू दास महंत और राजा उर्फ रामाशंकर पटेल के कहने पर कथित खोज से पहले दफन स्थल की जानकारी थी।पीडब्लू 3, श्रीमती संतारा बाई ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि आरोपी फोटो लाल ने स्वयं दफन स्थल की ओर इशारा किया था।अतः, अन्य अपीलकर्ताओं के कहने पर की गई कथित खोज अप्रासंगिक और अस्वीकार्य है।

64. चौथा, अभियोजन पक्ष एक सुसंगत और विश्वसनीय उद्देश्य स्थापित करने में विफल रहा है।दो परस्पर विरोधी उद्देश्य प्रस्तुत किए गए हैं, एक आरोपी फोटो लाल अनंत के दूसरे विवाह के कारण उत्पीड़न से संबंधित है, और दूसरा भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति से ₹2,00,000/- की राशि की मांग से संबंधित है। ये विरोधाभासी बयान अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं और कथित उद्देश्य को अविश्वसनीय बनाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

65. अब यह न्यायालय भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 और धारा 120 बी के तहत संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत आरोपों पर अलग-अलग विचार करेगा।ए. आई. पी. सी. की धारा 307 (हत्या) के संबंध में:आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी ने मृतक की जानबूझकर हत्या की थी।अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर यह स्पष्ट है कि:

• अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है।हालांकि कुछ परिस्थितियों, जिनमें कथित मकसद, ज्ञापन संबंधी बयान और बरामदगी शामिल हैं, पर प्रकाश डाला गया है, लेकिन परिस्थितियों की श्रृंखला न तो पूर्ण है और न ही पूरी तरह से आश्वस्त करने वाली है जिससे अपीलकर्ताओं के दोषी होने का अनिवार्य निष्कर्ष निकाला जा सके।

• अपीलकर्ताओं को मृत्यु का कारण बनने के वास्तविक कृत्य से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।

• शव के अत्यधिक सड़ जाने के कारण पोस्टमार्टम (एक्स पी/47) से मृत्यु का कारण निश्चित रूप से स्थापित नहीं हो सका।क्यूरी रिपोर्ट (एक्स पी/72) में केवल यह अनुमान लगाया गया है कि लाठी या छड़ से लगी चोटों के कारण मृत्यु हुई हो सकती है, लेकिन इसकी कोई निश्चित पुष्टि नहीं है।

• कई प्रमुख गवाहों के बयान काफी देरी से दर्ज किए गए, जिससे उनकी विश्वसनीयता और सटीकता पर संदेह पैदा होता है।

• कुछ अपीलकर्ताओं के कहने पर शव की कथित खोज और बरामदगी का श्रेय उन्हें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दफन स्थल की जानकारी पुलिस को आरोपी फोटो लाल अनंत के बयान से पहले ही मिल चुकी थी।

• उद्देश्य के विरोधाभासी संस्करण अभियोजन मामले को और कमजोर करते हैं।

उपरोक्त के आलोक में, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी विनोद कुमार अनंत की मृत्यु का कारण बने।इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।**बी. आई. पी. सी. की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) के संबंध में:––आईपीसी की धारा 120 बी के तहत** किसी गैरकानूनी कृत्य को अंजाम देने के लिए आरोपियों के बीच पूर्व निर्धारित सामान्य आशय का होना आवश्यक है।साक्ष्य की जांच के बारे में:

• अभिकथित षड़यंत्र का अनुमान मुख्य रूप से आरोपी फोटो लाल अनंत के ज्ञापन बयानों से लगाया गया है। हालांकि, इन कथनों पर भरोसा करना अनुचित है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत केवल वही भाग स्वीकार्य है जो किसी तथ्य की खोज की ओर ले जाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए शेष भाग अस्वीकार्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

• कोई भी स्वतंत्र, ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य सभी अपीलकर्ताओं की संलिप्तता वाली साजिश के अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता है।आरोपियों के बीच कथित वित्तीय लेन–देन और करार अप्रमाणित हैं।

• समान साक्ष्यों के आधार पर सह–आरोपी सोनू दास महंत की रिहाई इस बात को उजागर करती है कि अपीलकर्ताओं को आपराधिक साजिश से जोड़ने का कोई सुसंगत, स्वतंत्र आधार नहीं है।परिणामस्वरूप, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ताओं ने आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था।आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को भी यथावत नहीं रखा जा सकता है।

66. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करने में स्पष्ट रूप से विफल रहा है।साक्ष्य के सावधानीपूर्वक और समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों की श्रृंखला अपूर्ण, खंडित और विसंगतियों से भरी हुई है।परिस्थितिजन्य साक्ष्य को नियंत्रित करने वाले पाँच स्वर्णिम सिद्धांतों के अनुसार स्थापित किए जाने वाले आवश्यक परिस्थितियाँ—अर्थात्, (i) जिस परिस्थिति पर भरोसा किया जा रहा है वह आरोपी के अपराध का निर्णायक प्रमाण होनी चाहिए, (ii) यह पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए, (iii) सभी परिस्थितियाँ इस प्रकार जुड़ी होनी चाहिए कि एक श्रृंखला का निर्माण हो, (iv) श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए, और (v) परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जो आरोपी की निर्दोषता की हर तर्कसंगत परिकल्पना को खारिज कर दें—वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।कथित स्वीकारोक्ति, बरामदगी, उद्देश्य और अन्य

परिस्थितिजन्य कड़ियाँ कमियों, विलंबों और प्रक्रियात्मक खामियों से ग्रस्त हैं, जिसके कारण वे अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर पूरी तरह से इंगित करने वाली एक सुसंगत और अटूट श्रृंखला नहीं बनाती हैं।डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट सहित वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन पक्ष के विवरण की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने में विफल रहते हैं, और मृतक की पहचान और कथित अपराधबोधकारी वस्तुओं की बरामदगी में विसंगतियाँ पाई जाती हैं।उद्देश्य के परस्पर विरोधी संस्करण, प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी तथा अन्वेषण में कमियां सामूहिक रूप से अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर बना देती हैं।परिणामतः,संदेह का लाभ निश्चित रूप से अपीलकर्ताओं को मिलना चाहिए; ऐसी परिस्थितियों में किसी भी दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

67. तदनुसार, अपील सी. आर. ए. संख्या 555/2019, सी. आर. ए. संख्या 576/2019, सी. आर. ए. संख्या 848/2019 और सी. आर. ए. संख्या 1855/2019 सफल होती हैं और इन्हें स्वीकार किया जाता है।माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2019 को पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है।अपीलकर्ता, अर्थात् सरिताबाई अनंत (ए-2), श्रीमती। रेशम बाई कुर्रे (ए-4), धीरेंद्र कुमार बघेल (ए-5), दिनेश कुमार चौहान (ए-6), राजा उर्फ रमाशंकर पटेल (ए-7) और राजू दास महंत (ए-8) हैउन पर लगे सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

68. न्यायालय में कहा गया है कि अपीलार्थी जमानत पर हैं।दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437-ए (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए,

अपीलकर्ता, अर्थात् सरिता बाई अनंत (ए-2), श्रीमती रेशम बाई कुर्रे (ए-4), धीरेन्द्र कुमार बघेल (ए-5), दिनेश कुमार चौहान (ए-6), राजा उर्फ रामाशंकर पटेल (ए-7) और राजू दास महंत (ए-8) को दंड प्रक्रिया संहिता,, 1973 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000/- रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानती संबंधित न्यायालय के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही यह वचन भी देना होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उपर्युक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

69. इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख को अनुपालन तथा तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को तुरंत वापस भेजा जाना चाहिए।

सही /-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही /-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur